



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1257) पटना, शुक्रवार, 18 जुलाई 2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई 2025

सं० प्र०7-एल०पी०जी०(सी०जी०डी०)-02/2025-1505—भारत में तेजी से बढ़ती ऊर्जा की माँग को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के लिए प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किये जाने के फलस्वरूप शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025

1. परिचय

- 1.1. अवलोकन।**—भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और हमारी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए, अपने ईंधन मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाना स्थायी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त, प्राकृतिक गैस, एक वैकल्पिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन होने के नाते, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और स्थायी तरीके से हमारी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्रदान करने जा रहा है। खाने बनाने, औद्योगिक उपयोग और परिवहन के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के वैश्विक उपयोग के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार से मिलनेवाले प्रोत्साहन से प्राकृतिक गैस का उपयोग पसंदीदा ईंधन के रूप में लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ने 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के माध्यम से विभिन्न सीजीडी इकाइयों को 307 भौगोलिक क्षेत्रों को प्राधिकृत किया है, जो भारत की लगभग 99% जनसंख्या और 99% क्षेत्र आच्छादित करता है। बिहार सरकार ने घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में सीजीडी अवसंरचना विकास के महत्व को मान्यता दी है। घरेलू परिवारों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना पानी, बिजली आदि जैसी एक अनिवार्य सेवा बन गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सीजीडी सेवाओं को उपयोगिता का दर्जा दिया है। बड़े पैमाने पर जनता को पाइपलाइन प्राकृतिक गैस और परिवहन ईंधन की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सीजीडी नेटवर्क के विकास पर जोर देने हेतु बिहार राज्य में शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना के विकास के लिए अधिकृत इकाई (सीजीडी इकाई) को अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता और सरलीकरण लाना आवश्यक है। इसके तहत, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाइयों का दायित्व है कि वे घरेलू परिवारों एवं वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में और पाइप लाइन प्राकृतिक गैस (पी0एन0जी0) सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से मोटरगाड़ी (ऑटोमोबाइल) को ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करके शहरी गैस वितरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा लोक उपयोगिता परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 1.2. परिभाषाएँ।**—इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;
 - (ख) “बोर्ड” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;
 - (ग) “विनियम” से अभिप्रेत है पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम;
 - (घ) “पीएनजीआरबी” से अभिप्रेत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;
 - (ङ) “सीजीडी” से अभिप्रेत है शहरी गैस वितरण;
 - (च) “जीए” से अभिप्रेत है भौगोलिक क्षेत्र;
 - (छ) “एमडीपीई” से अभिप्रेत है मध्यम घनत्व पॉलीइथिलीन;
 - (ज) “प्राधिकृत इकाई” से अभिप्रेत है बिहार राज्य में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना स्थापित करने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, फर्म, कंपनी या सहकारी सोसाइटी;
 - (झ) “पैरा” से अभिप्रेत है इस नीति का पैरा;
 - (ञ) “स्थानीय निकाय” से अभिप्रेत है नगरपालिका क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद् या नगरपालिका बोर्ड, सुसंगत विधि के अधीन घोषित शहरी क्षेत्र (नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) में विकास प्राधिकरण या शहरी सुधार न्यास और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत (शहरी सुधार न्यास या विकास प्राधिकरण की अधिकारिता वाले क्षेत्र को छोड़कर);
 - (ट) “प्राधिकृत क्षेत्र” से अभिप्रेत है सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए पीएनजीआरबी विनियमों के तहत प्राधिकृत शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (इसमें इसके पश्चात् सीजीडी नेटवर्क कहा गया है) के लिए विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हो सकती हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके किसी भी संयोजन में, आर्थिक व्यवहार्यता और निकटता के मानदंडों के आधार पर, अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र, इसकी संपूर्णता में या उसके हिस्से में, एक नगर निगम या नगर पालिका

के भीतर, केंद्र या राज्य सरकार, गाँव, प्रखंड, तहसील, अनुमंडल या जिला या उसके किसी संयोजन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य शहरी क्षेत्र;

- (ठ) **“प्राकृतिक गैस”** से अभिप्रेत है बोर-होल से प्राप्त गैस और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन हैं और इसमें शामिल हैं— (i) तरल अवस्था में गैस, अर्थात्, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस, (ii) संपीडित प्राकृतिक गैस, (iii) सीएनजी या तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित पारदेशीय पाइप लाइनों के माध्यम से आयातित गैस, (iv) प्राकृतिक गैस के रूप में गैस हाइड्रेट से प्राप्त गैस, (v) कोयला सीमों से प्राप्त मीथेन, अर्थात्, कोयला बेड मीथेन, लेकिन इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन के सहयोग से प्राप्त हीलियम शामिल नहीं है;
- (ड) **“शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क”** से अभिप्रेत है गैस पाइपलाइनों का एक परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क और एक थोक आपूर्ति उच्च दबाव मुख्य संचरण से मध्यम दबाव वितरण ग्रिड में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए तथा बाद में घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसर तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले सेवा पाइपों तक के लिए तथा विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित सी एन जी स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले संबंधित उपकरण; “सीजीडी नेटवर्क का विकास” से अभिप्रेत है शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, बनाना, संचालित या विस्तारित करना;
- (ढ) **“पाइप प्राकृतिक गैस”** (इसमें इसके पश्चात् पीएनजी कहा गया है) से अभिप्रेत है घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक खंडों में ग्राहकों द्वारा खपत के लिए सीजीडी नेटवर्क के भीतर पाइपलाइन, सोपानी या किसी अन्य अनुमत साधन/प्रणाली के माध्यम से परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस। इसमें संपीडन से पहले ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन को आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस भी शामिल है;
- (ण) **“संपीडित प्राकृतिक गैस”** या **“सीएनजी”** से अभिप्रेत है वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस, आमतौर पर गैसीय स्थिति में रहते हुए 200 से 250 बार तक के दबाव से संपीडित होती है;
- (त) **“सीएनजी स्टेशन”** से अभिप्रेत है फिलिंग स्टेशन जहाँ संपीडित प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए एक या अधिक वितरण इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं;
- (थ) **“सीजीडी इकाई”** से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ, फर्म, कंपनी या सहकारी सोसाइटी, जिसे विक्रेता या वितरक से भिन्न किसी भी नाम से जाना जाता है या संदर्भित किया जाता है, और परिष्करण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, आयात और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के निर्यात में लगे होने या शामिल होने का इरादा रखता है, जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाना, या नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना या एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना और संचालन करना शामिल है;
- (द) **“कार्य योजना”** से अभिप्रेत है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या, सीएनजी स्टेशनों की संख्या और सीजीडी प्राधिकार विनियमों की अनुसूची-घ के अनुसार प्राधिकार पत्र में उल्लेखित इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन नेटवर्क;
- (ध) **सड़कों के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी)** आमतौर पर उस अवधि को संदर्भित करती है जिसके दौरान ठेकेदार या सेवा प्रदाता परियोजना के पूरा होने और सौंपने के बाद सड़क निर्माण में किसी भी दोष या मुद्दों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है;
- (न) **“उपयोग का अधिकार (आरओयू) या मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू)”** से अभिप्रेत है भूमि का वह क्षेत्र या हिस्सा जिसके भीतर पाइपलाइन ऑपरेटर या मालिक ने कानून के सुसंगत उपबंधों के माध्यम से या भूमि के मालिक या एजेंसी जिसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और संचालित करने के लिए भूमि की अधिकारिता है, के साथ समझौते के अनुसार अधिकार प्राप्त किया है;
- (प) **“सीजीएस”** से अभिप्रेत है, शहरी गेट स्टेशन;
- (फ) **“डीआरएस”** से अभिप्रेत है, जिला विनियमन स्टेशन;
- (ब) **“एमआरएस”** से अभिप्रेत है मीटरिंग और विनियामक स्टेशन;
- (म) **“लाईन विभाग”** लाईन विभाग से अभिप्रेत है कि इस नीति के उद्देश्य हेतु लाईन विभाग, बिहार सरकार के किसी विभाग एजेंसी या प्राधिकार जिसका की योजना निर्धारण, अनुमोदन, सुविधा उपलब्ध कराने या City Gas Distribution (CGD) के कार्य से सीधे तौर पर कार्यात्मक, विनियामक, प्रशासनिक या संचालन की भूमिका से सीधे संबद्ध हो, उसे प्रेषित कर सकता है।

(य) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम या उसके तहत बनाई गई नियमावली या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम, नियमावली या विनियमों में, उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

1.3. सिटी गैस वितरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल।—भारत सरकार ने 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए, सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस आवंटित की है, जो कि सीजीडी क्षेत्र के घरेलू (पाइप प्राकृतिक गैस) और परिवहन (संपीडित प्राकृतिक गैस) खंडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयातित प्राकृतिक गैस (तरलीकृत प्राकृतिक गैस — एलएनजी) की तुलना में सस्ती है और इसे बिना किसी कटौती श्रेणी में रखा गया है। सरकार द्वारा गैस की खपत बढ़ाने के लिए कई अन्य पहल की गई हैं।

1.4. सीजीडी क्षेत्र में नवीनतम विकास।—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी और एनजी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के साथ देश भर में प्राकृतिक गैस की अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीजीडी नेटवर्क (बोली के 12वें दौर तक) के समग्र आच्छादन को 307 भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, जिन्हें विभिन्न सीजीडी इकाइयों को प्राधिकृत किया गया है, जिसमें भारत की लगभग 99% आबादी और 99% क्षेत्र आच्छादित हैं।

बिहार राज्य में, सीजीडी अवसंरचना 38 जिलों में छह सीजीडी इकाइयों के माध्यम से परिचालन में है, जिसमें पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकरण की तारीख से आठ वर्ष के भीतर लगभग 30 लाख पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन और लगभग 650 सीएनजी स्टेशन प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। सीजीडी अवसंरचना के विस्तार के कारण 10,772 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता और लगभग 8,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का अवसर है।

पीएनजीआरबी ने पीएनजीआरबी विनियम 2010 (सीजीडी नेटवर्क के लिए अभ्यास कोड (संहिता) और सेवा की गुणवत्ता) के तहत नए पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए सेवा मानदंडों सहित सीजीडी अवसंरचना के विकास से संबंधित सुसंगत विनियमों को अधिसूचित किया है। इन विनियमों के अनुसार, सीजीडी इकाइयाँ मांग के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 90 दिनों के भीतर नए पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

विभिन्न राज्यों में सीजीडी अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने की आवश्यकता है। सामान्यतः, भूमि-स्वामित्व एजेंसियों, नागरिक एजेंसियों, नगर निगमों, जिला मजिस्ट्रेटों (सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु), अग्नि विभागों और अन्य प्राधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियाओं में अक्सर कई विभाग शामिल होते हैं, जिससे परियोजना निष्पादन एवं प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला को समग्र विकास में काफी देरी होती है।

इसे एक अधिदेश के रूप में पहचान की गयी है कि शहर/नगर की उत्कृष्ट योजना में शहरी गैस वितरण नेटवर्क शामिल होना चाहिए और इसमें सीएनजी स्टेशनों का प्रावधान होना चाहिए। नगर योजना विभाग/नगर पालिकाएँ/निगम/नगर और नगर विकास प्राधिकरण/पंचायतें, आदि को भवन की योजना को अनुमोदित करते समय पीएनजी अवसंरचना को शामिल करने के लिए आवश्यक प्रावधान करना चाहिए।

2. नीति का उद्देश्य।— इस नीति का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

1. प्रतिबद्ध कार्य योजना को निष्पादित करने के लिए सीजीडी इकाइयों की सहायता करके बिहार राज्य में सीजीडी अवसंरचना का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
2. नीतिगत ढांचा और आवश्यक सहायता तंत्र प्रदान करके सीजीडी इकाइयों के लिए समयबद्ध तरीके से अनुमति/मंजूरी/शूलक को, मानकीकृत और एक समान बनाना।
3. बिहार में प्राकृतिक गैस को हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देना और औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भारत की प्रतिबद्धताओं में योगदान मिलता हो।
4. परिसंपत्ति की अखंडता को बनाए रखते हुए प्राकृतिक गैस की सुरक्षित संचालन और विश्वसनीय, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सीजीडी संस्थाओं की सहायता करना।

राज्य सरकार, नीति के माध्यम से, सीजीडी नेटवर्क के विकास में तेजी लाने और घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का ईंधन के रूप में और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का परिवहन क्षेत्र के लिए उपयोग को बढ़ाने का प्रयास करेगी एवं मूल्य वर्धित सेवाओं और अवसरों के लाभों के साथ राज्य भर में सीजीडी अवसंरचना के आच्छादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सीजीडी का लाभ यथाशीघ्र आमजन तक पहुँचे।

3. राज्य स्तरीय सीजीडी नीति ।—

3.1. नोडल पदाधिकारी।—

- 3.1.1 **राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी ।—** राज्य स्तर पर बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नोडल पदाधिकारी होंगे। इस नीति में निर्धारित समय-सीमा से परे अनुमति या अनुमोदन प्राप्त करने में देरी के मामले में, सीजीडी इकाई, मामले को राज्य नोडल पदाधिकारी तक बढ़ा सकेगी।
- 3.1.2 **जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी ।—** जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नोडल पदाधिकारी होगा। जिला नोडल पदाधिकारी इस नीति के तहत कर्तव्यों का निर्वहन तेजी से और समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करते हुए करेगा।
- 3.1.3 **अपर जिला नोडल पदाधिकारी ।—** संबंधित लाइन विभाग से अपर जिला नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित कार्यपालक अभियंता, सीजीडी इकाई द्वारा प्रस्तुत सभी उपयोग के अधिकार (आरओयू) और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) आवेदनों को प्राप्त करने और स्वीकार करने, संयुक्त सर्वेक्षण कराने, जीर्णोद्धार प्रभार का आंकलन लगाने, या बैंक गारंटी (बीजी) राशि का निर्धारण करने, और पाइपलाइन बिछाने की गतिविधियों के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। जीर्णोद्धार कार्य और गुणवत्ता जाँच के संतोषजनक पूरा होने पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करेगा। पदाधिकारी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, सभी आवेदनों, अनुमोदनों, सर्वेक्षणों और जीर्णोद्धार गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखेगा, और सीजीडी परियोजना के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों को समाधान के लिए जिला नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। शहरी स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उपयोग के अधिकार एवं मार्गाधिकार की अनुमति, आवेदनों के अग्रसारण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी कार्य संबंधित शहरी स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालक पदाधिकारी में निहित होंगे।
- 3.1.4 **सहकारी समितियों, स्वायत्त निकायों और पीएसयू की संपत्तियों के लिए नोडल पदाधिकारी ।—** सहकारी निकाय, स्वायत्त निकाय या पीएसयू का जिले में तैनात सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी यथास्थिति उस सहकारी निकाय, स्वायत्त निकाय या पीएसयू से संबंधित संपत्तियों के लिए नोडल पदाधिकारी होगा।
- 3.1.5 **प्रसार तंत्र ।—** सभी जिला नोडल पदाधिकारी और अपर जिला नोडल पदाधिकारी अनुमोदन देने के लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपयोग के अधिकार (आरओयू) या मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए अनुमति से संबंधित देरी के मामलों में, मामले को सबसे पहले समाधान के लिए जिला नोडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा। यदि इस स्तर पर समाधान नहीं होता है, तो इसे समय पर समाधान के लिए राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी तक बढ़ाया जाएगा। हालाँकि, जिला विनियमन स्टेशनों/मीटरिंग और विनियामक स्टेशनों/विस्पीडन इकाइयों/गंधीकरण स्टेशनों/कार्यालय स्थान या संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशनों के लिए भूमि के आवंटन से संबंधित देरी के मामलों में, मुद्दे को सीधे समाधान के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी को बढ़ाया जाएगा।
- 3.1.6 **प्रायोगिकी एकीकरण और अनुश्रवण ।—** सभी अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुश्रवण के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड लागू किया जाएगा, जो किसी भी देरी की कुशल ट्रैकिंग और स्वचालित प्रसार को सक्षम करेगा। यह प्राधिकार के सभी स्तरों पर समय पर हस्तक्षेप और सुव्यवस्थित संचार सुनिश्चित करेगा।

3.2. अनुश्रवण समिति ।—

- 3.2.1 राज्य स्तर पर राज्य शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसी) के साथ प्रत्येक जिले में एक जिला शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (डीसीजीएमसीसी) की स्थापना की जाएगी। ये समितियाँ सभी शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाइयों को शामिल करते हुए मासिक आधार पर अनुमतियों की प्रगति की निगरानी और संबंधित मुद्दों का हल निकालने के लिए उत्तरदायी होंगी।
- 3.2.2 **जिला शहरी गैस अनुश्रवण एवं सहयोग समिति (डीसीजीएमसीसी) ।—** डीसीजीएमसीसी में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाएगा, डीसीजीएमसीसी के अध्यक्ष किसी भी विशेषज्ञ को सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत होगा जो विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने या सीजीडी कार्यान्वयन के तकनीकी, कानूनी या परिचालन पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

| पदनाम | भूमिका |
|--|------------|
| जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| उप विकास आयुक्त (डीडीसी) | सदस्य |
| अपर जिला समाहर्ता | सदस्य |
| नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय | सदस्य |
| प्रमंडलीय वन पदाधिकारी | सदस्य |
| कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) | सदस्य |
| कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) | सदस्य |
| कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) | सदस्य |
| कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| जिला परिवहन पदाधिकारी | सदस्य |
| अपर जिला दण्डाधिकारी, आपदा प्रबंधन | सदस्य |
| परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) | सदस्य |
| प्राधिकृत इकाई का प्रतिनिधि | सदस्य |
| जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। | सदस्य सचिव |

नोट : अध्यक्ष तकनीकी, नियामक या परिचालन मामलों को पता करने के लिए आवश्यक दो अतिरिक्त विशेषज्ञों या पदाधिकारियों तक सहयोजित करने का अधिकार रखता है।

- 3.2.3 **राज्य स्तरीय शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसीसी)।**— सिटी गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडीएन) को राज्य स्तर पर लागू किये जाने एवं उसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसीसी) जिम्मेदार होंगे एवं उसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

| पदनाम | भूमिका |
|---|---------|
| विकास आयुक्त | अध्यक्ष |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | संयोजक |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग | सदस्य |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| क्षेत्रीय प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) | सदस्य |
| प्राधिकृत इकाई का प्रतिनिधि | सदस्य |

नोट : अध्यक्ष तकनीकी, नियामक या परिचालन मामलों को जानकारी हेतु आवश्यकतानुसार दो अतिरिक्त विशेषज्ञों या पदाधिकारियों तक सहयोजित करने का अधिकार रखता है।

- 3.2.4 **सीजीडी विकास की राज्य-स्तरीय समीक्षा।**— सीजीडी नेटवर्क के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय बैठक महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार आयोजित की जानी चाहिए।
- 3.2.5 **सीजीडी विकास की जिला-स्तरीय समीक्षा।**— सीजीडी नेटवर्क की त्वरित प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला-स्तरीय बैठक महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार आयोजित की जानी चाहिए।

3.3. सामान्य शर्तें।—

- 3.3.1 **भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति।**— सीजीडी इकाई अपर जिला नोडल पदाधिकारी से भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगी, जो सड़क के स्वामित्व के लिए जिम्मेदार संबंधित लाइन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे नहीं होगा। यह प्रावधान सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होता है, जिसमें दोष देयता अवधि के तहत आने वाली सड़कें शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों में, ऐसी अनुमति देने की जिम्मेदारी संबंधित यूएलबी के कार्यपालक पदाधिकारी के पास होगी।

3.3.2 **सड़क जीर्णोद्धार I**— पाइपलाइनों को बिछाने/उतारने के बाद, सड़कों के जीर्णोद्धार या तो विभाग द्वारा की जाएगी जो उस सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है (यानी, विभागीय जीर्णोद्धार) या संबंधित सीजीडी इकाई द्वारा स्वयं (स्व-जीर्णोद्धार)। विभागीय जीर्णोद्धार और स्व-जीर्णोद्धार दोनों मामले में जीर्णोद्धार प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट हैं।

3.3.2.1 **विभागीय जीर्णोद्धार I**— विभागीय जीर्णोद्धार, संबंधित सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग द्वारा की गई सड़क जीर्णोद्धार को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) हो सकता है। राज्य की सड़कों के लिए, यह पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), या संबंधित नगरपालिका निकाय हो सकता है। विभागीय जीर्णोद्धार के मामलों में, संबंधित विभाग गैस वितरण पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क काटने की अनुमति देने से पहले तालिका-I में विनिर्दिष्ट दरों पर सेवा प्रदाताओं से जीर्णोद्धार प्रभार एकत्र करेगा।

तालिका 1 I— सड़कों के विभागीय जीर्णोद्धार की दरें

| क्र. सं. | विधि का प्रकार/सतह का प्रकार | सड़क जीर्णोद्धार प्रभार (आईएनआर)/वर्ग मीटर |
|---|------------------------------|--|
| ओपन कटिंग विधि/एचडीडी विधि/मोलिंग विधि | | |
| 1. | बीटी सड़कें— राजमार्ग | 4565.00 |
| 2. | बीटी सड़कें—ग्रामीण | 2077.00 |
| 3. | सीसी सड़कें— राजमार्ग | 3563.00 |
| 4. | सीसी सड़क— नगर पालिका | 2468.00 |
| 5. | सीसी सड़क—पंचायत | 2715.00 |
| 6. | फुट पाथ/पेवर ब्लॉक | 2775.00 |
| 7. | मिट्टी की सड़क/ढलान (शोल्डर) | 319.00 |

टिप्पणी :-

- उपरोक्त दरें वर्ष 2025-26 के लिए लागू हैं। इन दरों को हर तीन वर्ष में 10% तक संशोधित किया जाएगा, संशोधित दरें प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद के वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होंगी।
- उपरोक्त फीस जीएसटी और श्रम उपकर को छोड़कर हैं। जीर्णोद्धार प्रभार पर जीएसटी [वर्तमान में लागू दर पर] (समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन) और जीर्णोद्धार प्रभार के अतिरिक्त 1% की दर से श्रम उपकर का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित सड़क जीर्णोद्धार शुल्क का उपयोग केवल संबंधित लाइन विभाग द्वारा सीजीडी इकाई (सेवा प्रदाता) से जीर्णोद्धार शुल्क वसूलने के उद्देश्य से किया जाएगा। संबंधित लाइन विभाग द्वारा किये गये जीर्णोद्धार कार्य के लिए लागत अनुमान्य और वास्तविक भुगतान पी0डब्ल्यू0डी0 कोड और बिहार वित्तीय नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अक्षरसः अनुपालन किया जाएगा।

3.3.2.2 **स्व-जीर्णोद्धार I**— स्व-जीर्णोद्धार उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जहां प्राधिकृत सीजीडी इकाई विहित मानकों और विनिर्देशों के अनुपालन में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क काटने वाले भागों का जीर्णोद्धार स्वतंत्र रूप से करती है। इकाई, जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की पूरी जिम्मेदारी लेती है।

प्राधिकृत सीजीडी इकाई सड़क-काटने वाले भागों की स्व-जीर्णोद्धार का विकल्प केवल अपर जिला नोडल पदाधिकारी के पूर्वानुमति से एवं सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए लागू स्व-जीर्णोद्धार दिशा-निर्देश का पालन करते हुए चुन सकेगी, बशर्ते कि वे सड़क के जीर्णोद्धार के लिए कुल अनुमानित सड़क जीर्णोद्धार लागत के 10% के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करें, जैसा कि तालिका 2 में वर्णित है। पीबीजी को एक वर्ष के लिए वैध रहना चाहिए और संबंधित सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सीजीडी इकाई को सड़क को उसके मूल स्वरूप में जीर्णोद्धार करना होगा और अपनी लागत पर जीर्णोद्धार की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। संतोषजनक जीर्णोद्धार (और

पुनः जीर्णोद्धार, यदि आवश्यक हो) होने पर, पीबीजी को सेवा प्रदाता को लाईन विभाग या ULB द्वारा NOC प्रदान किये जाने के उपरांत 15 दिनों के अंदर सेवा प्रदाता को PBG वापस कर दिया जाएगा।

यदि सीजीडी इकाई विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सड़क के जीर्णोद्धार करने में विफल रहती है या उपयोगिताओं को नुकसान पहुँचाती है और उसे ठीक नहीं करती है, तो संबंधित विभाग जीर्णोद्धार में हुई क्षति या दोषों को दूर करने की लागत को आच्छादित करने के लिए निष्पादन बैंक गारंटी का उपयोग करेगा।

तालिका 2 निष्पादन बैंक गारंटी-स्व जीर्णोद्धार

| क्र. सं. | विधि के प्रकार/सतह के प्रकार | निष्पादन बैंक गारंटी शुल्क आई एन आर/वर्ग मी० में |
|-----------------------|------------------------------|--|
| खुली कटाई विधि | | |
| 1 | बीटी सड़कें- राजमार्ग | 456.00 |
| 2 | बीटी सड़कें-ग्रामीण | 208.00 |
| 3 | सीसी सड़कें- राजमार्ग | 356.00 |
| 4 | सीसी रोड-नगरपालिका | 247.00 |
| 5 | सीसी रोड-पंचायत | 271.00 |
| 6 | फुट पाथ/पेवर ब्लॉक | 278.00 |
| 7 | मिट्टी की सड़क/ढलान | 32.00 |

टिप्पणी :-

- उपरोक्त दरें वर्ष 2025-26 के लिए लागू हैं। इन दरों को हर तीन वर्ष में 10% तक संशोधित किया जाएगा, संशोधित दरें प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद के वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होंगी।
- उपरोक्त फीस जीएसटी और श्रम उपकर को छोड़कर हैं। जीर्णोद्धार प्रभार पर जीएसटी [वर्तमान में लागू दर पर] (समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अध्वधीन) और जीर्णोद्धार प्रभार के अतिरिक्त 1% की दर से श्रम उपकर का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए।

3.3.3 **जीर्णोद्धार के लिए तकनीकी विनिर्देश।**— सड़क और पुल कार्यों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) मानकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के विनिर्देश खुदाई और जीर्णोद्धार विधि के तहत किए गए सड़क जीर्णोद्धार के लिए मूलभूत दिशानिर्देशों के रूप में काम करेंगे। आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सड़क सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीजीडी इकाई द्वारा संबंधित लाईन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश अनुपालन किया जाएगा।

3.3.4 **पाइपलाईन बिछाने हेतु खुदाई जीर्णोद्धार।**— भूमिगत पाइप लाईन बिछाने की अनुमति विशेष रूप से खुदाई और जीर्णोद्धार विधि के तहत दी जाएगी। विभागीय जीर्णोद्धार के मामले में, सीजीडी इकाई तालिका 1 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार संबंधित लाइन विभाग को सड़क जीर्णोद्धार प्रभार का भुगतान करेगी। स्व-जीर्णोद्धार के लिए, सीजीडी इकाई कुल सड़क जीर्णोद्धार लागत के 10% की राशि की निष्पादन बैंक गारंटी संबंधित लाइन विभाग को प्रस्तुत करेगी, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है। स्व-जीर्णोद्धार के मामले में प्रतिभूति जमा सीजीडी इकाई द्वारा संतोषजनक जीर्णोद्धार की पुष्टि करते हुए, लाइन विभाग के संबंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

अनुमतियाँ निम्नलिखित में वर्गीकृत की जाएंगी।—

3.3.4.1 **विभागीय जीर्णोद्धार।**—

- सड़क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- सड़कों के विभागीय जीर्णोद्धार की लागत की गणना तालिका 1 में यथा विनिर्दिष्ट “सड़कों के विभागीय जीर्णोद्धार के लिए दर” के आधार पर की जाएगी, और सीजीडी इकाई भुगतान की विहित रीति के माध्यम से अग्रिम राशि जमा करेगी।

3.3.4.2 **स्व-जीर्णोद्धार।**—

- जीर्णोद्धार कार्य सीजीडी इकाई द्वारा ही किया जाएगा।

- तालिका 2 में उल्लेखित कुल सड़क जीर्णोद्धार लागत के 10% की राशि की निष्पादन बैंक गारंटी, संबद्ध सीजीडी इकाई द्वारा संबंधित लाइन विभाग को देय होगी। निष्पादन बैंक गारंटी अधिमानतः संबंधित लाइन विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले प्रस्तुत की जाएगी।
 - सीजीडी इकाई द्वारा सड़क जीर्णोद्धार कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की पुष्टि करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अपर जिला नोडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी, शहरी क्षेत्रीय निकाय द्वारा जारी किये जाने के 15 दिनों के अंदर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) विमुक्त कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण सड़कों के लिए, विभागीय जीर्णोद्धार लागू शर्तों के अध्यक्षीन पसंदीदा विकल्प होगा। जीर्णोद्धार शुल्क के लिए भुगतान का तरीका संबंधित प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।
- 3.3.5 उपयोगिता क्षति से बचने के लिए भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार सभी विभागों के साथ 'कॉल बिफोर यू डिग' एप का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। 'कॉल बिफोर यू डिग' एप से एसएमएस/ईमेल अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्खननकर्ताओं और परिसंपत्ति मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा और इसमें क्लिक-टू-कॉल विकल्प होंगे। इससे योजनाबद्ध उत्खनन को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी खुदाई से पहले संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया गया है।
- 3.3.6 **भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के तरीके।**— भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए खुली खाई और खाई रहित विधि की अनुमति है। हालांकि, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई/क्षति को कम करने के लिए जहां भी संभव हो, इकाई द्वारा क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी)/मैनुअल मिलिंग विधि पर विचार किया जाएगा।
- 3.3.7 **सड़क क्षति की मरम्मत और निष्पादन बैंक गारंटी वैधता।**— भूमिगत गैस पाइपलाइनों को बिछाने के दौरान सड़कों को नुकसान और गड्ढों को भरने का कार्य संबंधित सीजीडी इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर की जाएगी। संतोषजनक जीर्णोद्धार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक पूर्णता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरांत सड़क क्षति की मरम्मत 12 महीने की अवधि तक मान्य होगा। निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता सड़क क्षति की मरम्मत की अवधि के उपरांत 28 दिनों तक मान्य रहेंगी।
- 3.3.8 संबंधित जिले के क्षेत्राधिकार के भीतर एक बार में पूरे प्रस्तावित पाइपलाइन नेटवर्क के लिए पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, सीजीडी इकाई को किसी भी समय कुल अनुमत लंबाई के 20% या 5 किलोमीटर, जो भी कम हो, से अधिक की खुदाई करने की अनुमति नहीं है। सीजीडी इकाई को एक चरणबद्ध कार्य योजना, संबंधित प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसकी एक प्रति जिला नोडल पदाधिकारी को देनी चाहिए। प्रारंभिक चरण के संतोषजनक समापन पर, संबंधित सीजीडी इकाई बाद के चरण के लिए उत्खनन के साथ आगे बढ़ सकेगी।
- 3.3.9 सीजीडी इकाई जमा किये गए आवेदन के अनुसार किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए वापसी योग्य निष्पादन बैंक गारंटी अग्रिम रूप से जमा करेगी।
- 3.3.10 **सड़कों के किनारे और उसके पार सीजीडी पाइपलाइन बिछाना।**— किसी भी सड़क के किनारे पाइपलाइन बिछाने के लिए, प्राधिकृत सेवा प्रदाता कंपनी खुली कट विधि या मोलिंग विधि या क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) विधि का विकल्प चुन सकेगी। हालांकि, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख नगरपालिका सड़कों को पार करने के लिए आम तौर पर खुली कट विधि की अनुमति नहीं दी जाएगी; और वहाँ केवल क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) विधि या मोलिंग विधि का ही पालन किया जाएगा। राज्य सरकार के विभाग/एजेंसी के संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुमति से केवल छोटी ग्रामीण सड़कों के मामले में क्रॉसिंग के लिए खुली कट विधि की अनुमति दी जा सकेगी।
- 3.3.11 मानसून के दौरान मोलिंग/एचडीडी (क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग)/ट्रेंचलेस विधि के माध्यम से गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदक सभी सुरक्षा और संरक्षा उपाय करते हुए और यदि कोई नुकसान होता हो तो उसके तत्काल जीर्णोद्धार की योजना बनाए।

- 3.3.12 किसी भी हिस्से में सड़कों के नीचे बिछाई जाने वाली गैस पाइपलाइनों की संख्या, जिसके लिए अनुमति दी गई है, सीजीडी इकाई की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी। संबंधित लाइन विभाग (यथा आरसीडी/आरडब्ल्यूडी) और सीजीडी इकाई मौजूदा अवसंरचना में व्यवधानों को कम करते हुए पाईप लाइन अधिष्ठापन के समय तकनीकी और नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे।
- 3.3.13 सीजीडी इकाई गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान भूमिगत उपयोगिताओं को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतेगी। सीजीडी इकाई की लापरवाही के कारण हुई किसी भी नुकसान की स्थिति में, यह पूरी तरह से अपनी लागत पर नुकसान को ठीक करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा, यदि उपयोगिता स्थानों की गलत पहचान के कारण किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपयोगिता को कोई नुकसान होता है, तो सुधार की जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी। इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए जिला नोडल पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा।
- 3.3.14 पाइपलाइन स्थापन के लिए कोई सड़क खुदाई शुरू करने से पहले, सीजीडी इकाई उचित स्थल पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, दूरसंचार लाइनों, विद्युत आपूर्ति और अन्य पाइपलाइनों सहित मौजूदा भूमिगत उपयोगिताओं और प्रतिष्ठानों का मार्ग मानचित्र और सुसंगत विवरण प्राप्त करेगी। सुचारु समन्वय और देरी को कम करने के लिए, प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में मौजूदा उपयोगिताओं के साथ प्रत्येक एजेंसी, विभाग, प्राधिकरण या इकाई एक ही संपर्क बिंदु (एसपीओसी) को नामित करेगी, जिसके साथ सीजीडी इकाई भूमिगत उपयोगिताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीधे समन्वय करेगी।
- 3.3.15 सीजीडी इकाई खुदाई करने से पहले ऐसी भूमिगत उपयोगिताओं से संबंधित पर्यवेक्षी प्राधिकरण को सूचित करने के लिए भी जिम्मेदार होगी।
- 3.3.16 मौजूदा भूमिगत उपयोगिता और गैस पाइपलाइन को स्थानांतरित करने की लागत, जहां भी आवश्यक हो, अनुरोध करने वाली एजेंसी/प्राधिकरण/सीजीडी इकाई द्वारा वहन की जाएगी।
- 3.3.17 प्रत्येक भूमि या सड़क के स्वामित्व वाले विभाग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी सीजीडी से संबंधित कार्यों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु एक अपर जिला नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेगा, जो कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे का नहीं होगा। यह पदाधिकारी सीजीडी गतिविधियों के लिए समन्वय, अनुमोदन और निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।
- 3.3.18 सड़को में सुधार/चौड़ीकरण या फलाईओवर/पुल के निर्माण की स्थिति में सड़को के स्वामित्व से संबंधित प्राधिकार विस्थापन से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन जिला स्तर के अनुश्रवण समिति को समर्पित करेगा। समिति की अनुशंसा के उपरान्त संबंधित प्राधिकार विस्थापन संबंधी सूचना जारी करेगा और विस्थापन तथा पुनर्स्थापन संबंधी सभी खर्चों का वहन सीजीडी इकाई द्वारा वहन किया जाएगा।
- 3.3.19 सीजीडी इकाई राज्य सरकार और सभी संबंधित हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित करेगी।
- 3.4. राज्य सीजीडी नीति की प्रयोज्यता :-**
- 3.4.1 यह नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, राज्य प्राधिकरणों, सभी भूमि/सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों पर लागू होगी, जिनमें नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड, औद्योगिक संवर्धन निकाय, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), बिहार आवास बोर्ड और नगर विकास प्राधिकरण शामिल हैं, जो सुसंगत कानून के तहत घोषित नगर क्षेत्र में हैं (नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर), और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत (नगर, सुधार ट्रस्ट या विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के तहत आनेवाले क्षेत्र को छोड़कर), जल संसाधन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और सभी लागू निकाय जो सीजीडी नेटवर्क में शामिल हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं है।
- 3.4.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का कोई भी प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी उपयोग का अधिकार (आरओयू) सुविधा/अनुमति मांगने/प्राप्त करने के लिए पात्र है। हालांकि, इस प्रकार दी गई अनुमति की प्रवर्तनीयता उस अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्तिकारार में निहित/परिभाषित सेवा के प्रावधानों/दायरे की सीमा तक और उस उद्देश्य के लिए

- सीमित होगी जिसके लिए इसे समय-समय पर भारत सरकार या किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अध्यक्षीन स्वीकृत किया गया है।
- 3.4.3 चाहे विषयवस्तु के आधार पर या आशय के आधार पर उपयोग के अधिकार की सुविधा/अनुमति प्रदान करने का उद्देश्य अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति के दायरे को बढ़ाना नहीं है और ऐसी आरओयू अनुमतियाँ केवल सक्षम करने वाली प्रकृति की होंगी।
- 3.4.4 जब कभी अपेक्षित हो राज्य सरकार के अतिरिक्त विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
- 3.4.5 यदि पाईप लाईन वन क्षेत्र से होकर बिछाई जाती है, तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी की पूर्ण जवाबदेही होगी कि वह वन विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, भले ही सड़क राज्य सरकार के विभागों/स्थानीय निकायों/राज्य प्राधिकरणों की है। ऐसे मामलों में वन भूमि के उपयोग से संबंधित भारत सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देश एवं नियमों लागू होंगे।

3.5. उपयोग के अधिकार/मार्गाधिकार के लिए आवेदन प्रस्तुत करना।—

- 3.5.1 भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के लिए आवेदन संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी को अधिमानतः पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), या संबंधित सड़क के संचालन, रखरखाव और विकास के लिए उत्तरदायी कोई अन्य उपयुक्त विभाग के कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की अधिकारिता वाले क्षेत्रों में, संबंधित यूएलबी के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3.5.2 **सीजीडी पाइपलाइन बिछाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकताएँ।—** आवेदन निर्धारित प्रारूप (सामान्य आवेदन पत्र या सीएएफ) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें शामिल होंगे :
- क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति।
- ख) स्थानीय स्तर पर एकमार्ग योजना और “शेपफाइल फार्मेट (.Shp)” या “कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल)” फार्मेट में गूगल अर्थ/ऑटोकैड मानचित्र। मानचित्र में स्थान, मार्ग और भूमि/संपत्ति के स्वामित्व का विवरण होना चाहिए जहाँ पाइपलाइन बिछाई जानी है।
- ग) पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित पद्धति के साथ-साथ क्षेत्रवार और समयवार अनुसूची विनिर्दिष्ट करने वाली विस्तृत कार्य योजना (उदाहरण के लिए, क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी), खुली खाई खोदना या दोनों)।
- घ) खाई के आयामों (लंबाई, चौड़ाई, गहराई), पाइपलाइन की गहराई और अन्य प्रासंगिक विनिर्देशों के बारे में जानकारी।
- ङ) सीजीडी इकाई सभी प्रपत्रों, विवरणों और दस्तावेजों के साथ आवेदन की एक सॉफ्ट प्रति भी प्रस्तुत करेगी।
- 3.5.3 **वचनबंध।— आवेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुष्टि करने वाले वचनबंध।—**
- i. सड़कों, वाहनों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान सभी निवारक उपाय किए जाएंगे।
- ii. मरम्मती, लागत और मुआवजे सहित पाइपलाइन परिचालन के दौरान किसी भी खतरे, क्षति या रिसाव के लिए पूर्ण दायित्व।
- iii. कार्य के निष्पादन के बाद सड़क और आसपास के क्षेत्रों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने की प्रतिबद्धता।
- iv. वर्तमान पुलियों और पुलों में उपयोगिता सेवा का प्रावधान तबतक नहीं किया जा सकेगा जबतक की उसमें पूर्व से डक्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि ऐसा प्रावधान पूर्व में न किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी इसके लिए अलग से जल निकासी या नदियों को पार करने का प्रावधान अपने खर्च पर करेगा। ऐसी व्यवस्था रेलिंग या पुलों की संरचना की दीवार (Parapets) पर की जा सकेगी, इसके लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकार से अनुमति लेगा।
- v. यदि परियोजना पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करती है तो सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी या अनुमति प्राप्त करने का आश्वासन।
- vi. अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करना।

- vii. **शास्ति स्वीकृति:** वचनबंधों का पालन करने में विफलता पर शास्ति लगेगा, जिसमें कार्य निलंबन, अनुमतियों का प्रतिसंहरण और निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती शामिल हो सकती है।
- 3.5.4 **आवेदन प्रसंस्करण समयसीमा** I— नामित लाइन विभाग का नोडल पदाधिकारी, जो कार्यपालक अभियंता और शहरी स्थानीय निकायों के मामले में कार्यकारी पदाधिकारी के पद से नीचे का नहीं हो, अपर जिला नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन 15 दिनों के भीतर और किसी भी परिस्थिति में सीजीडी इकाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के बाद भी प्रक्रिया नहीं किया गया है। यदि इस 30 दिन की अवधि के भीतर न तो अनुमति दी जाती है और न ही स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है, तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को आगे की समीक्षा और विचार के लिए अध्यक्ष-सह-जिला नोडल पदाधिकारी को मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।
- 3.5.5 **लंबित आवेदनों की समीक्षा** I— जिला मजिस्ट्रेट बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए मासिक आधार पर सभी लंबित आवेदनों की समीक्षा करेंगे।
- 3.5.6 **अनुपालन** I— प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अनुपालन सहित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमावली और विनियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।
- 3.5.7 **स्वामित्व** I— सीजीडी इकाई के पास लागू कानूनों के अनुसार परिचालन उद्देश्यों के लिए केवल उपयोगकर्ता का अधिकार (आरओयू) होगा। सड़क या भूमि का स्वामित्व जहाँ पाइपलाइन स्थापित की गई है, संबंधित प्राधिकार के पास रहेगा।
- 3.5.8 खुदाई और आरओयू अनुमति देने पर, संबंधित लाइन विभाग (जैसे आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचडी, आदि) के अपर जिला नोडल पदाधिकारी आवेदक सीजीडी इकाई को सूचित करेंगे और जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रति प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों में अन्य एजेंसियों को आरओयू अनुमति देते समय जहां गैस पाइपलाइन पहले से मौजूद है, अपर जिला नोडल पदाधिकारी क्षेत्र में मौजूदा पाइपलाइन के साथ सीजीडी इकाई को सूचित करेंगे और संबंधित सीजीडी इकाई को आरओयू अनुमति की एक प्रति प्रेषित करेंगे।
- 3.5.9 **आवधिक नीति समीक्षा** I— हितधारक प्रतिपुष्टि, प्रौद्योगिकी में प्रगति और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए राज्य शहरी गैस अनुश्रवण समिति द्वारा इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
- 3.6. पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया** I—
- 3.6.1 सीजीडी इकाई संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी को या शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के मामले में, कार्यपालक पदाधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट की अग्रिम प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी। आवेदन प्राप्त होने पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी या संबंधित यूएलबी का कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा लागू हो, एक व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और 15 दिनों के भीतर सीजीडी इकाई के नामित प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद, तालिका 1 या तालिका 2 के अनुसार विभागीय जीर्णोद्धार प्रभार या निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने, प्रावधान के अनुरूप सभी आवश्यक दस्तावेजों जमा करने और इस नीति में निर्धारित अन्य प्रासंगिक शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन सीजीडी इकाई को आवश्यक अनुमति दी जा सकेगी।
- 3.6.2 **व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना और संसूचना** I— संबंधित लाइन विभाग, जिसके नियंत्रण में प्रस्तावित सड़क है, पंद्रह (15) कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति के लिए अनुरोध करने वाली सीजीडी इकाई के साथ निम्नलिखित तथ्यों को सूचित करेंगे :
- प्रस्तावित जीर्णोद्धार का प्रकार, क्या संबंधित विभाग द्वारा या अनुरोध करने वाली सीजीडी इकाई द्वारा किया जाना है।
 - पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित विधि चाहे खुली, कटिंग विधि, या क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) और मोलिंग विधि।
 - प्रस्तावित जीर्णोद्धार शूलक या निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के संबंध में सिफारिश।
- इस संसूचना की प्राप्ति पर संबंधित सीजीडी इकाई सात (7) दिनों के भीतर आवश्यक पीबीजी या विभागीय जीर्णोद्धार प्रभार, जैसा लागू हो, जमा करेगी।
- 3.6.3 विहित जीर्णोद्धार प्रभार और/या पीबीजी प्रस्तुत करने और अनुरोध करने वाली सीजीडी इकाई द्वारा व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट की स्वीकृति पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी

सीजीडी इकाई के आवेदन प्रस्तुत करने के एक (1) महीने के भीतर गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देंगे।

- 3.6.4 **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या जीर्णोद्धार प्रभार प्रस्तुत करना।**— आवेदक आवश्यक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या जीर्णोद्धार प्रभार, जैसा लागू हो, संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में सड़क स्थित है को प्रस्तुत करेंगे। आवेदक जिला नोडल पदाधिकारी को प्रस्तुत करने की रसीद की एक प्रति भी प्रदान करेंगे।
- 3.6.5 अपर जिला नोडल पदाधिकारी, जो संबंधित लाइन विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे का नहीं हो, या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा लागू हो, निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या जीर्णोद्धार प्रभार के भुगतान एवं व्यवहार्यता प्रतिवेदन की स्वीकार्यता पर संबंधित अपर जिला नोडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देंगे।
- 3.6.6 यदि प्रारंभिक आवेदन जमा करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपर जिला नोडल पदाधिकारी या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आरओयू/आरओडब्ल्यू की अनुमति नहीं दी जाती है, तो सीजीडी इकाई जिला नोडल पदाधिकारी को शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध करते हुए एक औपचारिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करके मामले को बढ़ा सकेगी, जिसमें स्वीकृति का अनुरोध किया जा सकेगा। सीजीडी इकाई विहित प्रक्रियाओं के अनुसार जिला नोडल पदाधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट से स्पष्ट प्राधिकार प्राप्त होने तक किसी भी पाइपलाइन बिछाने की गतिविधियों के साथ आगे नहीं बढ़ेगी।

3.7. अनापत्ति प्रमाणपत्र।—

- 3.7.1 सीजीडी इकाई द्वारा स्व-जीर्णोद्धार की स्थिति में, संबंधित लाइन विभाग का अपर जिला नोडल पदाधिकारी या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यपालक पदाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण और विहित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करेगा, जो सहायक अभियंता के पद से नीचे का नहीं होगा। तकनीकी विशेषज्ञ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और संतोषजनक जीर्णोद्धार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट और एनओसी के आधार पर, अपर जिला नोडल पदाधिकारी या यूएलबी को कार्यकारी पदाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सीजीडी इकाई को 15 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
- 3.7.2 मुख्यमार्गीय, उप-मुख्यमार्गीय और अन्य उच्च यातायात सड़कों के लिए, उत्खनन हेतु जिम्मेदार इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अस्थायी जीर्णोद्धार के उपाय, जिसमें बैकफिलिंग, संघनन और अस्थायी सड़क सतह का अनुप्रयोग शामिल है, उत्खनन के 24 से 48 घंटे के भीतर पूरा किया जाय। इन सड़कों के लिए स्थायी जीर्णोद्धार को प्राथमिकता के रूप में माना जाएगा और इसे सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
- 3.7.3 इकाई, पाइपलाइन बिछाने और बिछाई गई पाइपलाइन के हिस्से पर जीर्णोद्धार के बाद जीर्णोद्धार के निरीक्षण और एनओसी जारी करने के लिए नामित पदाधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगी।
- 3.7.4 नामित पदाधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी सीजीडी इकाई से लिखित सूचना के 07 दिनों के भीतर जीर्णोद्धार के काम का निरीक्षण करेगा और 07 (सात) दिनों के भीतर, सुधार यदि कोई हो, के लिए सलाह देगा।
- 3.7.5 सीजीडी इकाई निर्देश या टिप्पणियों के अनुसार जीर्णोद्धार को सुधारेगी और 10 दिनों के भीतर नामित पदाधिकारी को सूचित करेगी।
- 3.7.6 इसके बाद नामित पदाधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी फिर से काम का निरीक्षण करेंगे और 07 (सात) दिनों के भीतर जीर्णोद्धार के लिए एनओसी जारी करेंगे।
- 3.7.7 यदि इकाई द्वारा संतोषजनक जीर्णोद्धार और निरीक्षण की सूचना के 07 दिनों के भीतर नामित पदाधिकारी द्वारा फिर से निरीक्षण करने के बाद भी नामित पदाधिकारी द्वारा एवं बिना किसी भी टिप्पणी के बाद भी एनओसी नहीं दी जाती है, तो इकाई, जिला नोडल पदाधिकारी को मामले को प्रस्तुत कर सकेगी।
- 3.7.8 किसी प्राधिकार के क्षेत्राधिकार के तहत पूरे क्षेत्र के लिए एनओसी जारी करने के बाद, संबंधित प्राधिकार पीबीजी को वापस कर देगा या संबंधित सी0जी0डी0 इकाई के अनुरोध

- पर बाद की अनुमति के लिए पीबीजी जमा के रूप में रख सकेगा एवं बाद की अनुमति हेतु पीबीजी माना जा सकेगा।
- 3.7.9 नामित प्राधिकारी/अपर जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एक विनिर्दिष्ट अवधि (जैसे, एक वर्ष) के लिए मान्य रहेगी जब तक कि जीर्णोद्धारित क्षेत्र में कोई पर्याप्त उपांतरण या क्षति नहीं देखी जाय या रिपोर्ट न की जाय।
- 3.7.10 मौजूदा सीएनजी स्टेशन से समीप सीएनजी उपकरण की स्थापन की सुविधा के लिए सीएनजी स्टेशनों के मौजूदा भूखंड के आकार में मामूली परिवर्तन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट सम्यक् तत्परता के बाद सीधे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगा। चूंकि इन खुदरा दुकानों या सीएनजी स्टेशनों को पहले ही सुसंगत पदाधिकारियों से मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए न्यूनतम अतिरिक्त जाँच के साथ एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।
- 3.7.11 **उपयोग के अधिकार/मार्गाधिकार के प्रसंस्करण और अनुमोदन में देरी के लिए प्रेषण तंत्र I**—यह प्रेषण तंत्र शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाइयों के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमतियों के प्रसंस्करण और अनुमोदन में देरी का हल निकालने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। यह तंत्र एक संरचित प्रेषण मार्ग के साथ प्रत्येक चरण में समय पर अनुमोदन और स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

| चरण | उत्तरदायी प्राधिकारी | समय सीमा | कार्रवाई | अगला स्तर | समाधान समय सीमा |
|--|--|---|---|----------------------|--|
| आवेदन जमा करना | सीजीडी इकाई अपर जिला नोडल पदाधिकारी | 0 दिन | आरओयू/आरओडब्ल्यू आवेदन प्रस्तुत करना | लागू नहीं | लागू नहीं |
| संयुक्त सर्वेक्षण | संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी/ सहायक अभियंता और सीजीडी इकाई के प्रतिनिधि | आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर | चिह्नित सड़क का संयुक्त सर्वेक्षण करना | लागू नहीं | लागू नहीं |
| सड़क जीर्णोद्धार प्रभार का आकलन | अपर जिला नोडल पदाधिकारी | आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर | जीर्णोद्धार के प्रकार के आधार पर सड़क जीर्णोद्धार प्रभार का आकलन करना और सीजीडी इकाई को अधिसूचित करना | लागू नहीं | लागू नहीं |
| स्व-जीर्णोद्धार के मामले में विभागीय जीर्णोद्धार प्रभार या पीबीजी जमा करना | सीजीडी इकाई | अपर जिला नोडल पदाधिकारी की अधिसूचना के अनुसार | सड़क जीर्णोद्धार प्रभार या निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करना | लागू नहीं | लागू नहीं |
| पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन | अपर जिला नोडल पदाधिकारी | आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर | नीति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन प्रदान करना | जिला नोडल पदाधिकारी | मामला प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर |
| मामला जिला नोडल पदाधिकारी को भेजना | जिला नोडल पदाधिकारी | यदि अनुमोदन में 30 दिनों से अधिक की देरी होती है। | लंबित आवेदन की समीक्षा करना और अनुमोदन करना | राज्य नोडल पदाधिकारी | मामला प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर |
| मामला राज्य नोडल पदाधिकारी को भेजना | राज्य नोडल पदाधिकारी | यदि मुद्दा 40 दिनों से अधिक तक समाधान नहीं होता हो। | लंबित मुद्दे की अंतिम समीक्षा कर समाधान या प्रतिक्रिया देना। | लागू नहीं | लागू नहीं |

3.8. जिला विनियमन स्टेशनों (डीआरएस), मीटरिंग और विनियमन स्टेशनों (एमआरएस), विसंपीडित इकाइयों (डीसीयू), गंधीकरण स्टेशनों, शहरी गैस स्टेशन (सीजीएस) और सीजीडी इकाइयों हेतु कार्यालय स्थलों के लिए भूमि आवंटन

3.8.1 आवंटन के लिए विचार की गई भूमि का प्रकार :-

- (i) पुरानी परती
- (ii) गैर मज़रूआ (आम, खास और मालिक)
- (iii) शैक्षणिक संस्थान
- (iv) अस्पताल परिसर
- (v) नगर निगम और नगर परिषद
- (vi) खाता
- (vii) पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- (viii) ग्राम पंचायत
- (ix) प्रखण्ड/अंचल/थाना/कारागार परिसर
- (x) परिवहन विभाग.
- (xi) औद्योगिक प्राधिकरण
- (xii) विद्युत विभाग
- (xiii) राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी प्रकार की भूमि

3.8.2 **भूमि का सीमांकन** ।- राज्य सरकार और/या प्राधिकरण या संबंधित लाइन विभाग को किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए किसी भी क्षेत्र या उसके हिस्से को आरक्षित घोषित करने का अधिकार होगा और उस स्थिति में, वह क्षेत्र या उसका हिस्सा केवल उस विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए आवंटित किया जाएगा जब तक कि सरकारी प्राधिकार द्वारा उसे परिवर्तित या अनारक्षित न कर दिया जाय।

भूमि के चिन्हिकरण एवं प्रस्ताव की जिम्मेदारी CGD इकाइयों की होगी, हालांकि CGD इकाई भूमि की चिन्हिकरण करने में जिला प्रशासन की मदद ले सकेगा।

3.8.3 **भूमि आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकार** ।- जिला विनियमन स्टेशन (डी आर एस), मीटर विनियमन स्टेशन (एम आर एस) एवं संपीडित इकाई (डी सी यू), गंधीकरण स्टेशन और सीजीडी इकाई हेतु कार्यालय स्थल की स्थापना के लिए सीजीडी इकाइयों को भूमि के आवंटन हेतु जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी होगा। यह आवंटन भूमि के स्वामित्व वाले विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के अध्वधीन होगा। उक्त भूमि आवंटन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी से सम्पर्क कर वांछित सहमति के उपरान्त आवंटित किये जायेंगे। जिला दण्डाधिकारी प्रत्येक ईकाई के लिए अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

3.8.4 **आवेदन की प्रक्रिया** ।- सीजीडी इकाई जिला नोडल पदाधिकारी को दबाव विनियमन स्टेशनों की स्थापना के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी जिसकी अग्रिम प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को दी जाएगी। जिसमें जिला विनियमन स्टेशन (डीआरएस) (लगभग 10 मीटर x 8 मीटर), मीटर रेगुलेटिंग स्टेशन (एमआरएस), विसंपीडित इकाई (डीसीयू) (लगभग 13 मीटर x 18 मीटर), गंधीकरण स्टेशन (20 मीटर x 18 मीटर), सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) और, सीजीडी इकाइयों के लिए एलएनजी/एल-सीएनजी हब/सीबीजी (मानदंड-अपेक्षित क्षेत्र के अनुसार) शामिल हैं किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है। आवेदन में विस्तृत डिजाइन, सुरक्षा नयाचार, तकनीकी विनिर्देश, स्थापना के लिए अनुमानित समयसीमा, प्रस्तावित स्थान को चिह्नित करने वाला मानचित्र और पीएनजीआरबी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति अवश्य शामिल होनी चाहिए।

3.8.5 **दबाव विनियमन स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुमति और पट्टा** ।- पाइपलाइन के साथ रणनीतिक स्थानों पर पाइप लाइन के साथ दबाव विनियमन स्टेशन जिनमें जिला विनियमन स्टेशन (डीआरएस), मीटरिंग विनियमन स्टेशन (एमआरएस), या विसंपीडित इकाइयाँ (डीसीयू), गंधीकरण स्टेशन शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; की स्थापना की अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों में सड़क के किनारे के क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, उपयोगिता क्षेत्र, सरकारी परिसर या अन्य उपयुक्त स्थल शामिल हो सकेंगे जैसा कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) इकाई के परामर्श से पहचान किया जाए। इन स्थलों का चयन सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देगा, पहुंच

सुनिश्चित करेगा, और मौजूदा अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान को कम करेगा।

शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अधिदेश के अनुसार जिला विनियमन स्टेशनों (डीआरएस) के पास गंधीकरण स्टेशनों की स्थापना के लिए 20 मीटर X 18 मीटर भूमि निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक डीआरएस के लिए एक गंधीकरण पंप की आवश्यकता के बिना, परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर चयनित डीआरएस स्थानों पर गंधीकरण पंप स्थापित किए जाएंगे। इन गंधीकरण स्टेशनों के लिए भूमि के आवंटन का समन्वय जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा भूमि के लिए जिम्मेदार संबंधित लाइन विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

प्रारंभिक पट्टा अवधि 25 वर्ष होगी, जिसमें आवश्यक अनुमोदन के अधीन, उस क्षेत्र की आवासीय श्रेणी की भूमि के न्यूनतम मूल्यांकन रजिस्टर (एमवीआर) के 5% वार्षिक पट्टा पर किराया निर्धारित किया जाएगा। पट्टा किराया भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल को या उससे पहले या अनुबंध की समाप्ति से पहले, जो भी पूर्व हो, वार्षिक रूप से किया जाएगा। पट्टे की अवधि को सरकार के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक पट्टा किराया शूल्क आवासीय श्रेणी की भूमि के प्रचलित एमवीआर के आधार पर हर तीन साल में पुनरीक्षण के अधीन होगा। जिला मजिस्ट्रेट संबंधित सीजीडी इकाई से पट्टा किराया भुगतान प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार नामित प्राधिकारी होगा।

- 3.8.6 **कार्य स्थल के लिए सरकारी भूमि का आवंटन ।**— उपलब्धता के अधीन, कार्यालय स्थल की स्थापना के लिए तेल कंपनियों/सीजीडी इकाई को सरकारी भूमि आवंटित की जा सकेगी। तेल कंपनियाँ/सीजीडी इकाई आवंटित भूमि से जुड़ी सभी लागतों का वहन करेगी। सरकारी भूमि पर विकसित किसी भी संरचना का स्थायी प्रकृति की होने की संभावना है। भूमि का आवंटन, लागू किराये या पट्टे के प्रभार के साथ, मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- 3.8.7 जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान में डीआरएस स्टेशन (10 मीटर X 8 मीटर) या डीसीयू स्टेशन (13 मीटर X 18 मीटर) के लिए भूमि के विशिष्ट प्रावधान शामिल हो। राज्य सरकार किसी भी स्थान पर पाइपलाइन के साथ सरकारी भूमि को आवंटित करेगी, जिसमें पीएनजी/सीएनजी की लागत को कम किए बिना सीजीडी इकाई की आवश्यकता के अनुसार सड़क के किनारे, सार्वजनिक पार्क, उपयोगिता क्षेत्र, सरकारी परिसर, नगरपालिका वार्डों/गांवों आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो ग्राहकों को ग्लीनर, स्वच्छ ईंधन की ओर आकर्षित करती है।
- 3.8.8 सीजीडी परियोजना को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, यदि कोई उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो जिला नोडल पदाधिकारी अधिग्रहण या पट्टा समझौतों के माध्यम से उपयुक्त निजी भूमि की पहचान करने और सुरक्षित करने में सहायता करेगा, सभी लागू विनियमों और मानकों का पालन करते हुए सीजीडी परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- 3.8.9 नोडल पदाधिकारी संबंधित प्राधिकरण/लाइन विभाग को सीजीडी इकाई के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त सर्वेक्षण के लिए निदेशित करेगी और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संयुक्त सर्वेक्षण भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगा, मौजूदा अवसंरचना पर संभावित प्रभावों का आकलन करेगा, और पर्यावरण नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में तस्वीरों और सुसंगत सहायक दस्तावेजीकरण के साथ विस्तृत निष्कर्ष शामिल होने चाहिए।
- 3.8.10 संबंधित स्थानीय प्राधिकार/संबंधित लाइन विभाग के अपर जिला नोडल पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिला नोडल पदाधिकारी वार्षिक किराया तय करेगा और इकाई को प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए किराया जमा करने और उसके बाद 03 साल के गुणकों में जमा करने के लिए सूचित करेगा।
- 3.8.11 डीआरएस/एमआरएस/डीसीयू की स्थापना के लिए उपयोग की गयी भूमि के वार्षिक किराए की गणना आवासीय आरक्षित मूल्य या आवासीय डीएलसी (जिला स्तरीय समिति) दर जो उस क्षेत्र में लागू हो जहाँ भूमि अवस्थित है, के 5% पर की जाएगी। “आवासीय आरक्षित मूल्य/आवासीय डीएलसी दर” की समीक्षा हर तीन वर्ष में की जाएगी, जिसमें मुद्रास्फीति के लिए किए गए समायोजन के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किराया उचित बाजार मूल्य को दर्शाता रहे।

- 3.8.12 सीजीडी इकाई संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को किराया जमा करेगी और जिला नोडल पदाधिकारी को सूचित करेगी।
- 3.8.13 जिला नोडल पदाधिकारी संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को किराया जमा करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर दबाव विनियमन स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।
- 3.8.14 डीआरएस/एमआरएस/डीसीयू के लिए भूमि खरीदते समय रजिस्ट्रीकरण प्रभार का भुगतान सीजीडी इकाई द्वारा वाणिज्यिक भूमि प्रकार के अनुसार किया जाएगा और भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र (सीयूएल) प्राप्त करने के लिए कृषि से वाणिज्यिक श्रेणी में भूमि के रूपांतरण के लिए कोई और शुल्क लागू नहीं होगा।
- 3.8.15 डीसीयू के अस्थायी स्थापना के मामले में आवश्यक हो तो अधिकतम 5 वर्ष की अवधि का अल्पकालिक पट्टा, स्टील पाइपलाइन बिछाने तक लागू होगी।
- 3.8.16 यदि आवेदन जमा करने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुमति नहीं दी जाती है, तो सीजीडी इकाई राज्य नोडल पदाधिकारी के समक्ष मुद्दा उठा सकेगी। राज्य नोडल पदाधिकारी आवेदन का निष्पादन करेगा और 7 दिनों के भीतर आवश्यक अनुमति देने के लिए संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को सिफारिश करेगा।
- 3.8.17 भूमि के अंतिम आवंटन और वार्षिक किराए के भुगतान के बाद ही पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।
- 3.8.18 भूमि को 25 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर जैसा है, जहाँ है के आधार पर आवंटित किया जाएगा, इसके साथ आगे विस्तार का प्रावधान होगा।
- 3.8.19 किसी विरोध के उत्पन्न होने की स्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य करेगा। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा और इसमें शामिल सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- 3.8.20 यदि आवंटी निर्धारित समय के भीतर किराए के प्रभार का भुगतान करने में विफल रहता है, अनुमोदित योजना के विपरीत निर्माण करता है, या उद्योगों के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलग्न होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास भूमि आवंटन को रद्द करने का अधिकार होगा।

3.9. सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि का आवंटन।—

- 3.9.1 सीजीडी इकाई अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में प्राधिकार प्रदान करने से पहले के 8 वर्षों के दौरान पीएनजीआरबी के लिए प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य योजना (एमडब्ल्यूपी) के हिस्से के रूप में सीएनजी खुदरा दुकानों की कुछ निश्चित संख्या स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 3.9.2 जिला नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमुख यातायात गलियारों (न्यूनतम 40 मीटर x 30 मीटर) पर संबंधित शहरी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान में सीएनजी स्टेशनों के लिए भूखंड हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- 3.9.3 सी0एन0जी0 स्टेशन को भूमि का आवंटन जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा। शहर की सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कों के भीतर प्रमुख यातायात गलियारों में एमडब्ल्यूपी पूरा करने के लिए आवश्यक भूखंडों को आवंटित किया जाएगा।
- 3.9.4 सीएनजी स्टेशनों के लिए भूमि के आवंटन का प्रावधान करने हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।
- 3.9.5 शहर/नगर के योजना चरण में सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि/भूखंड को चिह्नित करना और इसे आवास और शहरी परिनियोजन प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- 3.9.6 बस स्टैंड के योजना चरण में सीएनजी स्टेशनों के विकास के लिए भूमि/भूखंड को चिह्नित करना और इसे परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- 3.9.7 **शहरी स्थानीय निकायों की सड़क अवसंरचना में गैस पाइपलाइन अवसंरचना का समावेश।—** शहरी स्थानीय प्राधिकरण स्मार्ट सिटी और निविदा एसयूआरइ (शहरी सड़कों के निष्पादन के लिए विनिर्देश) के तहत परियोजनाओं सहित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय अन्य उपयोगिताओं के साथ गैस पाइपलाइन अवसंरचना के प्रावधान सदैव शामिल करेंगे।
- 3.9.8 **भवन योजना के अनुमोदन के समय स्थानीय निकायों द्वारा पीएनजी पाइपलाइनों/नेटवर्क को शामिल करने के प्रावधान।** नगर विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार योजना अनुमोदन चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस

पाइपलाइन अवसंरचना प्रदान करने के लिए उप-नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी। सभी सरकारी आवासों, अतिथि गृहों और कार्यालय भवनों में पीएनजी संयोजकता के प्रावधान होने चाहिए।

- 3.9.9 बिहार सरकार के सभी आवासीय क्षेत्र के भवन में पीएनजी का उपयोग करेंगे। वास्तुशिल्प डिजाइन चरण में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन अवसंरचना प्रदान करने के लिए सुसंगत भवन उप-नियमों को परिवर्तित किया जाएगा।

3.10. पसंदीदा हरित ईंधन के रूप में सीएनजी/एलएनजी को बढ़ावा देना।—

- 3.10.1 परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से सीएनजी/एलएनजी को पसंदीदा परिवहन ईंधन के रूप में अपनाना। राज्य परिवहन निगम सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी/एलएनजी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान वैकल्पिक ईंधन बेड़े में नई बसें खरीदते समय और रेट्रोफिटिंग करते समय सीएनजी/एलएनजी बसों को प्राथमिकता देंगे। सरकारी विभागों में उपयोग किए जा रहे/लगे वाहनों (कार, बसें, एम्बुलेंस, डिलीवरी वैन, माल वाहक, आदि) को सीएनजी वाहनों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा जहां सीएनजी बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।
- 3.10.2 अधिकृत क्षेत्र में सरकारी भवनों, दूरसंचार सेवा टावरों उद्योगों या अन्य प्रतिष्ठानों में डीजल जनरेटर का गैस जनरेटर के साथ संपरिवर्तन।— दूरसंचार टावर पूरे बिहार राज्य में स्थित हैं और पारंपरिक स्रोतों की बड़ी संख्या में प्राथमिक और बैकअप ऊर्जा खींचते हैं। डीजल जनरेटर सेट बिजली बैकअप के प्रदूषित करने वाले हैं और कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के साथ, एक आसान सा विकल्प उपलब्ध विकल्प डीजल आधारित जनरेटर से प्राकृतिक गैस आधारित जनरेटर पर स्विच करना है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जो कम लागत पर पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करेंगे। राज्य स्तरीय समिति उपयुक्त नियमों/विनियमों को लाकर डीजल सेटों को सीएनजी जनरेटरों में संपरिवर्तित करने को सुगम बनाने के लिए कदम उठाएगी।
- 3.10.3 गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषणकारी ईंधन पर प्रतिबंध।— औद्योगिक क्षेत्रों को गैस पाइपलाइन संपर्क से जुड़ने के लिए अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन औद्योगिक क्षेत्रों में जहां गैस पाइपलाइन संयोजकता विकसित की गई है, सभी प्रदूषणकारी ईंधन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अनुरूप अनुमोदित ईंधन की एक सूची अपनाई जा सकेगी। प्राकृतिक गैस के अधिक से अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे राष्ट्र को अपनी सीओपी-26 (पार्टियों का सम्मेलन) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- 3.10.4 सीएनजी/एलएनजी अपनाने का अनुश्रवण और प्रोत्साहन।— राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन, सरकारी वाहनों और औद्योगिक क्षेत्रों में सीएनजी/एलएनजी अपनाने की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक अनुश्रवण और रिपोर्टिंग ढांचा स्थापित करेगी। संपरिवर्तन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन किया जाएगा, और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हितधारकों को स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए सीएनजी/एलएनजी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
- 3.10.5 विपणन और जागरूकता अभियान।— सीजीडी इकाई जागरूकता अभियानों, इमारतों पर विज्ञापनों और होर्डिंग के प्रदर्शन, राजमार्गों पर सीएनजी दिशा सूचकों के प्रदर्शन के माध्यम से पीएनजी और सीएनजी के लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राहकों से संपर्क करेगी।

3.11. शिकायत निवारण तंत्र।—

- 3.11.1 जिला नोडल पदाधिकारी जनता/प्राधिकरण/सीजीडी इकाई द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों की मासिक समीक्षा करेगा।
- 3.11.2 जनता/प्राधिकरण/लाइन विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत को तीन (03) दिनों के भीतर संबंधित सीजीडी इकाई को अग्रेषित की जाएगी और सीजीडी इकाई इसका समाधान करेगी और प्रत्येक शिकायत के लिए सात (07) दिनों के भीतर जिला नोडल पदाधिकारी को अनुपालन प्रस्तुत करेगी।
- 3.11.3 सीजीडी इकाईयों द्वारा जिला नोडल पदाधिकारी को दर्ज की गई शिकायतों को तीन (03) दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और संबंधित प्राधिकारी

शिकायत का समाधान करेगा और सात (07) दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी को अनुपालन प्रस्तुत करेगा।

3.11.4 आम-जन, संबंधित प्राधिकार या CGD इकाई द्वारा शिकायत दर्ज किये जाने के उपरांत यदि जिला नोडल पदाधिकारी नियत समय सीमा के अंदर इसका निष्पादन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मामले को State City Gas Monitoring & Cordination Committee (SCGMCC) को समक्ष इस मामले पर पुनः विचार करने एवं उचित सामाधान निकालने हेतु अग्रसारित किया जाएगा।

3.11.5 **विवाद समाधान तंत्र**।—यदि CGD इकाईयों और बिहार सरकार के किसी लाईन विभाग के बीच या स्वयं CGD इकाईयों के बीच किसी मामले पर शहरी गैस वितरण नीति के कार्यान्वयन, संचालन या व्याख्या के संबंध में असहमति या मतभेद उत्पन्न होने पर CGD नीति के तहत सभी पक्ष सर्वप्रथम अनौपचारिक बात-चीत के माध्यम से मामले को शांतिपूर्ण समाधान या समझौता का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि आपसी सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की सूचना दिये जाने के तीस दिनों के अंदर सभी सम्बद्ध पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बनती है तो मामले को मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जाएगा। सभी पक्षों की आपसी सहमति से एक नियुक्त मध्यस्थ के पास विवाद को भेजा जाएगा। यदि सभी संबंध पक्ष तीस दिनों के अंदर किसी एक मध्यस्थ की नियुक्ति में असफल होते हैं तो सचिव, विधि विभाग मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।

Arbitration and conciliation act 1996 और इस संबंध में समय-समय पर संशोधित नियमों के आलोक में मध्यस्थ कार्यावाही संचालित करेंगे। मध्यस्थ द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, जिसपर लागू कानून के अंतर्गत विधिक उपचार उपलब्ध होगा। मध्यस्थ का स्थान पटना, बिहार में होगा और समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

3.12. कार्य स्थल पर सुरक्षा उपायों की व्यवस्था।—

3.12.1 सीजीडी इकाई गैस पाइपलाइन बिछाने से संबंधित स्थापन, उपरांत-स्थापन, रखरखाव और अन्य गतिविधियों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करेगी। यह नदियों और नहरों पर क्रॉसिंग सहित संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां भी लागू करेगी। निष्पादन के दौरान या उसके बाद जीवन या संपत्ति के किसी भी दुर्घटना या क्षति की स्थिति में, सीजीडी इकाई लागू विनियमों के अनुसार मामले पर ध्यान देने और उसका हल करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी के साथ सहयोग करेगी।

3.12.2 **आवश्यक सेवाओं की बहाली**।— आवश्यक सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, दूरसंचार लाइनों या बिजली की आपूर्ति के नुकसान की स्थिति में, संबंधित सीजीडी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जीर्णोद्धार के लिए किए गए सभी खर्च संबंधित सीजीडी इकाई द्वारा वहन किए जाएंगे। संबंधित राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों या राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित जीर्णोद्धार लागत के संबंध में निर्णय अंतिम होगा। गैस पाइपलाइन रिसाव, क्षति, या अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए सीजीडी इकाईयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों (ईआरवी) को परिवहन विभाग द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया की सुविधा सुगम बनाने और देरी को कम करने के लिए आपातकालीन वाहनों के रूप में पदनामित किया गया माना जाएगा।

3.12.3 **सुरक्षा मानकों का अनुपालन**।— सीजीडी इकाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित सभी सुरक्षा मानकों और उपायों का पालन करेगी, जैसा कि एनओसी, अनुमोदन या मंजूरी के निबंधन और शर्तों में उल्लेखित है। सड़क पर गैस पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना के बाद स्थापित कोई भी उपयोगिता, लागू मानदंडों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ गैस पाइपलाइन से सुरक्षित दूरी पर स्थापित की जाएगी। यदि गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले मौजूदा उपयोगिताएँ पूर्व से मौजूद हैं, सीजीडी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि पाइपलाइन को विहित मानकों के अनुपालन में पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ स्थापित किया जाए।

- 3.12.4 सार्वजनिक उपयोगिता की स्थिति और नोटिस का प्रदर्शन ।— सीएनजी मोबाइल कैस्केड वाहक वाहनों को सार्वजनिक उपयोगिता वाहनों के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीजीडी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कार्य स्थल पर उचित नोटिस प्रदर्शित किए जाएँ।
- 3.12.5 ओपन-कट प्रणाली दिशानिर्देश ।— जब गैस पाइपलाइन को ओपन-कट प्रणाली का उपयोग करके बिछाया जाना हो, तो क्षेत्र को ठीक से बैरिकेड किया जाना चाहिए, और पर्याप्त शोरिंग (टेकबन्दी) प्रदान की जानी चाहिए। काम इस तरह से किया जाना चाहिए कि यातायात में व्यवधान कम से कम हो। आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सड़क सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
- 3.12.6 दुर्घटनाओं, क्षति और अनधिकृत हस्तक्षेप के लिए दायित्व ।— सीजीडी इकाई को गैस पाइपलाइन नेटवर्क के निष्पादन या संचालन के दौरान अपने कार्यों, चूक या लापरवाही के परिणामस्वरूप किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसी अनधिकृत व्यक्ति या इकाई द्वारा गैस पाइपलाइन या संबंधित प्रतिष्ठानों को नुकसान की स्थिति में, सीजीडी इकाई एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकेगी जिससे पुलिस को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
पीएनजी प्रणाली में कोई भी अनधिकृत छेड़छाड़ या परिवर्तन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच के अधीन होगा, और यदि उपभोक्ता के कारण ऐसा होना पाया जाता है, तो दायित्व उनके ऊपर रहेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना निष्पादन या O&M क्रियाकलापों के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा सीजीडी कर्मियों को हुई किसी भी बाधा, उपद्रव या नुकसान को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा संचालन के खिलाफ अपराध माना जाएगा और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत समाधान किया जाएगा।
- 3.12.7 आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन ।— जिला प्राधिकार संबंधित में CGD इकाईय के सहयोग से जो उस भौगोलिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। सहयोग से आपदा प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन संबंधी नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह योजना गैस पाईप लाईन के रिसाव/क्षतिग्रस्त होने को संभावित खतरे से विशेषतः ध्यान देगा। इस तरह की आकिस्मिकता की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकार और CGD इकाई वर्ष में कम से कम एक बार संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे।
- 3.13. सीजीडी अवसंरचना अनुमोदन के लिए एकल-खिड़की ऑनलाइन पोर्टल ।—
शहरी गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, अगले छह महीनों के भीतर सीजीडी इकाईयों द्वारा एक एकल-खिड़की ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा। यह पोर्टल सीजीडी अवसंरचना विकास से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा।
यह ऑनलाइन प्रणाली अपर जिला नोडल पदाधिकारी और जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा सीएनजी स्टेशनों के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) अनुमति और भूमि आवंटन सहित जिला स्तर पर विभिन्न अनुमतियां प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।
जिला और राज्य दोनों स्तरों पर सभी संबंधित हितधारकों के पास एक कुशल, पारदर्शी और संरचित अनुमोदन कार्यप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी गई भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ पोर्टल तक पहुंच होगी।
- 3.14. नीतियों में पुनरीक्षण ।—
- 3.14.1 राज्य स्तरीय शहरी गैस अनुश्रवण एवं समन्वय समिति (एससीजीएमसीसी) की अनुशंसा के आलोक में नीतियों के किसी बिन्दुओं में सुधार करने अथवा संशोधन करने का अधिकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित होगा।
- 3.14.2 दरों को पुनरीक्षित/समायोजित करने, पीजीबी दर, पट्टा के नियम एवं शर्तों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा।
- 3.14.3 राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि-15.07.2025 से यह नीति लागू होगा।

बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 के हिन्दी के अधिसूचना प्रारूप में व्याख्यात्मक अंतर होने पर अंग्रेजी का अधिसूचना प्रारूप ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

पंकज कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

Food and Consumer Protection Department

Notification***The 15th July 2025***

No. Pra.7-LPG (CGD)-02/2025-1505/Food—In view of the rapidly growing energy demand in India, and in accordance with the provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006, as well as the imperative for clean and environmentally sustainable energy, natural gas is being promoted as a preferred alternative. Accordingly, the City Gas Distribution Policy, 2025, is hereby notified.

By the order of Governor of Bihar,
PANKAJ KUMAR,
Principal Secretary to the Government.

Bihar City Gas Distribution Policy, 2025**1. Introduction**

- 1.1. **Overview.**—India is an emerging economy with the world's largest population, and our energy demand is growing swiftly. To meet the energy demand, increasing the share of cleaner energy sources to its fuel mix is critical for having sustainable economic growth. In addition to renewable energy sources, natural gas, being an alternative cleaner fossil fuel, is going to play a significant role and provide solutions to the environmental challenges along with meeting our growing energy demands in a sustainable manner. Global use of natural gas as fuel for cooking, industrial use, and transport has resulted in significant change in environmental conditions. With the impetus coming from the Government of India, natural gas is steadily growing as a fuel of choice.

The Government of India (GOI) has set a target to increase the share of natural gas in the country's primary energy mix from 6.2% to 15% by 2030. The Government of India through Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has authorized 307 Geographical Areas to various CGD Entities, covering about 99% of India's population and 99% of the areas.

The Government of Bihar recognized the importance of the development of CGD infrastructure in urban, rural, and industrial areas for providing eco-friendly clean energy to domestic, industrial, commercial, and transport segments. Providing natural gas to domestic households has become an essential service, like water, electricity, etc., for which the Central Government has granted utility status to CGD services. To put thrust on the development of the CGD network for providing the uninterrupted supply of pipeline natural gas and transport fuel to the public at large, it is necessary to bring uniformity, clarity, and simplification of process for providing permissions to the authorized entity (CGD entity) for the development of City Gas Distribution (CGD) infrastructure in urban, rural, and industrial areas in the state of Bihar.

Under this, the City Gas Distribution (CGD) Entities have the obligation to develop the City Gas Distribution network to supply Piped Natural Gas (PNG) to domestic households and commercial & industrial segments and Compressed Natural Gas (CNG) as fuel to automobiles through CNG Stations. The City Gas Distribution Project has been categorized by the Government of India as a public utility project.

1.2. **Definitions**

In this Policy, unless the context otherwise requires,

- (a) **"Act"** means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006
- (b) **"Board"** means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, established under sub-section (1) of section 3 of the Act.
- (c) **"Regulations"** means regulations made by the Board, under PNGRB Act, 2006.
- (d) **"PNGRB"** means Petroleum & Natural Gas Regulatory Board.
- (e) **"CGD"** means City Gas Distribution
- (f) **"GA"** means Geographical Area
- (g) **"MDPE"** means Medium Density Polyethylene
- (h) **"Authorized Entity"** means any person, association of persons, firm, company or cooperative society, by whatsoever name called or referred to, authorized by PNGRB, to set up City Gas Distribution (CGD) infrastructure in the State of Bihar.
- (i) **"Para"** means the Para of this Policy.
- (j) **"Local Body"** means a Municipal Corporation, Municipal Council or Municipal Board in a Municipal area, a Development Authority or Urban Improvement Trust in an urban area declared under the relevant law (excluding the Municipal area), and Gram Panchayat for Rural areas (excluding the area under the jurisdiction of an Urban Improvement Trust or a Development Authority).
- (k) **"Authorized Area"** means the specified geographical area for a city or local natural gas distribution network (hereinafter referred to as CGD network) authorized under PNGRB regulations for laying, building, operating or expanding the CGD network which may comprise of following categories, either individually or in any combination thereof, depending upon the criteria of economic viability and contiguity, namely, geographic area, in its entirety or in part thereof, within a municipal corporation or municipality, any other urban area notified by the Central or the State Government, village, block, tehsil, sub-division or district or any combination thereof.
- (l) **"Natural Gas"** means gas obtained from bore-holes and consisting primarily of hydrocarbons and includes- (i) gas in liquid state, namely, liquefied natural gas and Regasified liquefied natural gas, (ii) compressed natural gas, (iii) gas imported through transnational pipe lines, including CNG or liquefied natural gas, (iv) gas recovered from gas hydrates as natural gas, (v) methane obtained from coal seams, namely, coal bed methane, but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons.
- (m) **"City or Local natural gas distribution network"** means an interconnected network of gas pipelines and the associated equipment used for transporting natural gas from a bulk supply high pressure transmission main to the medium pressure distribution grid and subsequently to the service pipes supplying natural gas to domestic, industrial or commercial premises and CNG stations situated in a specified geographical area "development of a CGD network" means laying, building, operating or expanding a city or local natural gas distribution network.
- (n) **"Piped Natural Gas"** (hereinafter referred to as PNG) means natural gas transported through pipelines, cascades, or any other permitted mode within a CGD network for consumption by customers in domestic, commercial, or industrial segments. It also includes natural gas supplied to an online CNG station before compression.
- (o) **"Compressed Natural Gas" or "CNG"** means natural gas used as fuel for vehicles, typically compressed to a pressure ranging from 200 to 250 bars while remaining in a gaseous state.

- (p) **"CNG station"** means filling station where one or more dispensing units are provided for sale of compressed natural gas.
- (q) **"CGD entity"** means a person, association of persons, firm, company or cooperative society, by whatsoever name called or referred to, other than a dealer or distributor, and engaged or intending to be engaged in refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing, import and export of petroleum, petroleum products and natural gas including laying of pipelines for transportation of petroleum, petroleum products and natural gas, or laying, building, operating or expanding city or local natural gas distribution network or establishing and operating liquefied natural gas terminal;
- (r) **"Work programme"** means number of domestic PNG connections, number of CNG stations and Inch-kilometer of steel pipeline network as mentioned in the authorization letter as per Schedule-D of CGD Authorization regulations.
- (s) The **Defect Liability Period (DLP)** for roads typically refers to the duration during which the contractor or service provider is responsible for repairing any defects or issues in the road construction after the completion and handover of the project.
- (t) **"Right Of Use (ROU) or Right Of Way (ROW)"** means the area or portion of land within which the pipeline operator or owner has acquired the right through the relevant provisions of law or in accordance with the agreement with the land owner or agency having jurisdiction over the land to lay and operate the natural gas pipelines.
- (u) **"CGS"** means, City gate stations.
- (v) **"DRS"** means, District Regulating Station.
- (w) **"MRS"** means, Metering and Regulating Station.
- (x) **"DCU"** means, Decompression Unit.
- (y) **"Line Department"** For the purpose of this Policy, **"line department"** shall refer to any department, agency, or authority of the Government of Bihar that has a direct functional, regulatory, administrative, or operational role in the planning, approval, facilitation, or oversight of City Gas Distribution (CGD) activities.
- (z) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

1.3. **Initiatives taken by Govt of India to promote the City Gas Distribution sector.**— Government of India (GOI) has set a target to increase the share of natural gas in country's primary energy mix from 6.2% to 15% by 2030. In order to promote the expansion of City gas networks and enhance the usage of natural gas, the Government has allocated domestically produced natural gas, which is cheaper than imported natural gas (Liquefied Natural Gas - LNG), to meet the requirement of Domestic (Piped Natural Gas) and Transport (Compressed Natural Gas) segments of CGD sector and it has been kept under no cut category. Many other initiatives have been taken by the Government to increase gas consumption.

1.4. **Recent Developments in City Gas Distribution Sector**—Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP&NG) along with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is focusing on the development of natural gas infrastructure across the country. The overall coverage of CGD networks (up to the 12th round of bidding) has been expanded to 307 Geographical Areas which has been authorized to various CGD Entities, covering about 99% of India's population and 99% of the areas.

In the state of Bihar, CGD infrastructure is operational in 38 districts through six CGD entities, with a commitment to provide approximately 30 lakh PNG (domestic)

connections and around 650CNG stations within eight years from the date of authorization by PNGRB. There is an investment potential of ₹ 10,772 crores and an employment generation opportunity for around 8,000 persons due to the expansion of CGD infrastructure.

PNGRB has notified relevant regulations related to CGD infrastructure development, including service norms for providing new PNG connections under the PNGRB (Code of Practice and Quality of Service for CGD Networks) Regulations, 2010. As per these regulations, CGD entities are obligated to provide new PNG connections within 90 days from the date of demand registration.

There is a need to facilitate the development of CGD infrastructure across various states. Generally, permissions are required from land-owning agencies, civic agencies, municipal corporations, district magistrates (for No Objection Certificates to set up CNG stations), fire departments, and other authorities. These processes often involve multiple departments, leading to significant delays in project execution and the overall development of the natural gas value chain.

It has been identified as a mandate that city/town planning master plans should include the City Gas Distribution network and should have the provision of CNG stations. The Town Planning Departments / Municipalities / Corporations / City & Town Development Authorities / Panchayats, etc. should make necessary provisions to include PNG infrastructure while giving building plan approvals.

2. **Objective of the Policy**

This policy aims at achieving the following objectives.—

1. To ensure faster implementation of CGD infrastructure in the Bihar State by supporting the CGD entities to execute the Committed Work Programme.
2. Make permissions/clearances/charges, standardized and uniform in a time bound manner for the CGD entities by providing policy framework and necessary support mechanism.
3. To promote the adoption of natural gas in Bihar as a green and clean fuel and encourage its use for industrial, commercial, transport, and household purposes, thereby contributing to India's commitments to reducing carbon emissions.
4. To assist CGD entities in ensuring safe operations and the reliable, uninterrupted supply of natural gas by maintaining asset integrity.

The state government, through the policy, will endeavour to accelerate the development of the CGD network and increase the use of natural gas as a fuel in the form of Piped Natural Gas (PNG) for domestic, commercial, and industrial sectors and compressed natural gas (CNG) for the transport sector and take necessary steps to increase the coverage of CGD infrastructure across the state along with benefits from value-added services and opportunities. It is primarily intended that the benefit of the CGD should reach the public at the earliest.

This policy will come into effect from

3. **State Level City Gas Distribution Policy.—**

3.1. **Nodal Officers**

- 3.1.1 **State Level Nodal Officer.**—The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of the Food and Consumer Protection Department of Bihar shall be the Nodal Officer at the state level. In case of delays in obtaining permissions or approvals beyond the timelines prescribed in this policy, the CGD entity may escalate the matter to the State Nodal Officer.
- 3.1.2 **District Level Nodal Officer.**—The District Magistrate shall be the Nodal Officer at District level. The district Nodal Officer shall discharge the duties under this policy ensuring rapid and timely approvals.

- 3.1.3 **Additional District Nodal Officer.**— The Executive Engineer, designated as the Additional District Nodal Officer from the relevant line department, shall be responsible for receiving and acknowledging all Right of Use (RoU) / Right of Way (RoW) applications submitted by the CGD entity, conducting joint surveys, estimating restoration charges, or determining Bank Guarantee (BG) amounts, and granting approvals for pipeline laying activities. Upon satisfactory completion of restoration work and quality checks, the Additional District Nodal Officer shall issue No Objection Certificates (NoCs). The officer shall provide technical support, maintain detailed records of all applications, approvals, surveys, and restoration activities, and submit periodic reports to the District Magistrate to ensure transparency and accountability in the execution of the CGD project. Matters requiring higher-level intervention shall be escalated to the District Nodal Officer for resolution. In areas under the jurisdiction of Urban Local Bodies (ULBs), the responsibility for granting Right of Use (RoU) or Right of Way (RoW) permissions, processing applications, and issuing No Objection Certificates (NOCs) shall lie with the Executive Officer of the respective ULB.
- 3.1.4 **Nodal Officer for Properties of Cooperatives, Autonomous Bodies, and PSUs.**—The senior most officer of the Cooperative body, Autonomous body or a PSU posted in the district shall be the Nodal Officer for the properties belonging to that Cooperative body, Autonomous body, or a PSU, as the case may be.
- 3.1.5 **Escalation Mechanism.**—All District Nodal Officers and Additional District Nodal Officers shall ensure compliance with the prescribed timelines for granting approvals. In cases of delay related to permissions for Right of Use (RoU) or Right of Way (RoW), the matter shall first be escalated to the District Nodal Officer for resolution. If unresolved at this stage, it shall be escalated to the State-Level Nodal Officer for timely resolution. However, in cases of delay related to the allotment of land for District Regulating Stations/ Metering and Regulating Stations/ Decompression Units/ Odorization Stations/ Office Space or Compressed Natural Gas Stations, the issue shall be directly escalated to the State Nodal Officer for resolution.
- 3.1.6 **Technology Integration and Monitoring.**—A centralized digital dashboard shall be implemented to monitor all approval processes, enabling efficient tracking and automatic escalation of any delays. This will ensure timely intervention and streamlined communication across all levels of authority.

3.2. **Monitoring Committee**

- 3.2.1 A District City Gas Monitoring & Coordination Committee (DCGMCC) shall be established in each district, along with a State City Gas Monitoring & Coordination Committee (SCGMCC) at the State level. These committees will be responsible for monitoring the progress of permissions and addressing related issues on a monthly basis, involving all City Gas Distribution (CGD) entities.
- 3.2.2 **District City Gas Monitoring & Coordination Committee (DCGMCC).**— The DCGMCC will comprise of the members as mentioned below, the Chairman of DCGMCC is authorized to co-opt any expert as necessitated to address specific challenges or provide guidance on technical, legal, or operational aspects of CGD implementation.

| Designation | Role |
|--|-----------|
| District Magistrate | Chairman |
| Superintendent of Police | Member |
| Deputy Development Commissioner (DDC) | Member |
| Additional District Collector | Member |
| Municipal Commissioners/Executive Officers, Urban Local Bodies | Member |
| Divisional Forest Officer | Member |
| Executive Engineer, Public Health Engineering Department (PHED) | Member |
| Executive Engineer, Road Construction Department (RCD) | Member |
| Executive Engineer, Rural Works Department (RWD) | Member |
| Executive Engineer, Water Resource Department | Member |
| District Transport Officer | Member |
| Additional District Magistrate, Disaster Management | Member |
| Project Director-National Highway Authority of India | Member |
| Representative of the Authorized Entity | Member |
| District Supply Officer, Food and Consumer Protection Department | Member |
| | Secretary |

Note: The Chairman retains the authority to co-opt up to two additional experts or officers as needed to address technical, regulatory, or operational concerns

3.2.3 **The State City Gas Monitoring & Coordination Committee (SCGMCC)**, responsible for overseeing the implementation and monitoring of the City Gas Distribution Network (CGDN) at the state level, will comprise the following members:

| Designation | Role |
|---|----------|
| Development Commissioner | Chairman |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Food and Consumer Protection Department | Convener |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Revenue and Land Reforms | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Urban Development & Housing Department | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Commercial Tax Department | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Transport Department | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Road Construction Department | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Rural Works Department | Member |
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Water Resources Department | Member |
| Regional Officer- National Highway Authority of India | Member |
| Representative of the Authorized Entity | Member |

Note: The Chairman retains the authority to co-opt up to two additional experts or officers as needed to address technical, regulatory, or operational concerns

3.2.4 **State-Level Review of CGD Development.**— A state-level meeting should be conducted at least once a month, or as deemed necessary, to ensure the expeditious development of the CGD network.

3.2.5 **District-Level Review of CGD Development.**— A district-level meeting should be held at least once a month, or as deemed necessary, to facilitate the swift progress of the CGD network.

3.3. General Conditions

- 3.3.1 **Permission for Laying Underground Gas Pipelines.**—The CGD Entity shall obtain the necessary permissions for laying underground gas pipelines from the Additional District Nodal Officer, who shall not be below the rank of Executive Engineer of the concerned line department responsible for the ownership of the road. This provision applies to all types of roads, including those under the Defect Liability Period. In areas falling under the jurisdiction of Urban Local Bodies (ULBs), the responsibility for granting such permissions shall rest with the Executive Officer of the concerned ULB.
- 3.3.2 **Road Restoration.**—After laying/ lowering of the pipelines, the restoration of roads shall be done either by the Department which is responsible for construction, operation, and maintenance of that road (i.e., Departmental Restoration) or by the respective CGD entity themselves (Self Restoration). Restoration charges in case of both Departmental Restoration and Self-Restoration are as specified below.
- 3.3.2.1 **Departmental Restoration.**—Departmental Restoration refers to road restoration undertaken by the department responsible for the construction, operation, and maintenance of the respective road. For example, for National Highways, it may be the National Highways Authority of India (NHAI), National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL). For State Roads, it may be the Road Construction Department (RCD), Rural Works Department (RWD), Public Health Engineering Department (PHED), or the concerned Municipal Body. In cases of Departmental Restoration, the respective department shall collect restoration charges from service providers as per the rates specified in Table-I before granting permission for road cutting to lay gas distribution pipelines.

Table 1: Rates for Departmental Restoration of Roads

| Sl. No. | Types of Method/Type of Surface | Road Restoration Charges (INR)/Sq. Mtr. |
|--|---|---|
| Open Cutting Method/ HDD Method/ Molling Method | | |
| 1 | Bituminous Roads (BT) Roads- Highway | 4565.00 |
| 2 | BT Roads-Rural | 2077.00 |
| 3 | Cement Concrete Roads (CC) Roads- Highway | 3563.00 |
| 4 | CC Road-Municipal | 2468.00 |
| 5 | CC Road-Panchayat | 2715.00 |
| 6 | Foot Paths/Paver Blocks | 2775.00 |
| 7 | Earthen Road/ Shoulder | 319.00 |

Note:

- The above rates are applicable for the year 2025-26. These rates shall be revised by 10 % every three years, with the revised rates coming into effect from April 1st of the year immediately after the completion of each three-year period.
- The above fees are exclusive of GST and Labour Cess. GST [at the currently applicable rate] on the Restoration Charges (subject to change as per the directions of the Government of India from time to time) and Labour Cess @ 1% must be paid in addition to the Restoration Charges.
- The Road Restoration Charges mentioned in the above table shall be used solely by the concerned line department for the purpose of

recovering restoration charges from the CGD Entity (Service Provider). The cost estimation and actual payment for the restoration work carried out by the concerned line department shall be done strictly in accordance with the relevant provisions of the PWD Code and the Bihar Financial Rules.

3.3.2.2 Self-Restoration.—Self-Restoration refers to the process where the authorized CGD entity independently undertakes the restoration of road-cutting portions after laying pipelines, in compliance with the prescribed standards and specifications. The entity assumes full responsibility for the quality and timely completion of the restoration work.

The authorized CGD entity may carry out self-restoration of roads only with prior approval from the concerned Additional District Nodal Officer and in compliance with applicable self-restoration guidelines for Public Utility Projects, provided they submit a Performance Bank Guarantee (PBG) equivalent to 10% of the total estimated road restoration cost for the applicable road type as detailed in Table 2. The PBG must remain valid for one year and shall be submitted to the department responsible for the construction, operation, and maintenance of the respective road.

The CGD entity must restore the road to its original profile and ensure the stability of the restoration at their own cost. Upon satisfactory restoration (and re-restoration, if required), the PBG shall be returned to the Service Provider within 15 days of the (No Objection Certificate) NOC issuance by the concerned line department or the ULB.

If the CGD entity fails to restore the road as per the specified standards or causes damage to utilities and does not rectify the same, the concerned department shall invoke the Performance Bank Guarantee to cover the costs for rectifying the damages or defects in restoration.

Table 2 Performance Bank Guarantee-Self Restoration

| Sl. No. | Types of Method/Type of Surface | Performance Bank Guarantee Charges in INR/ Sq. Mtr. |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Open, Cutting Method | | |
| 1 | BT Roads- Highway | 456.00 |
| 2 | BT Roads-Rural | 208.00 |
| 3 | CC Roads- Highway | 356.00 |
| 4 | CC Road-Municipal | 247.00 |
| 5 | CC Road-Panchayat | 271.00 |
| 6 | Foot Paths/Paver Blocks | 278.00 |
| 7 | Earthen Road/ Shoulder | 32.00 |

Note:

- The above rates are applicable for the year 2025-26. These rates shall be revised by 10% every three years, with the revised rates coming into effect from April 1st of the year immediately after the completion of each three-year period.
- The above fees are exclusive of GST and Labour Cess. GST[at the currently applicable rate] on the Restoration Charges (subject to change as per the directions of the Government of India from time to time) and Labour Cess @ 1% must be paid in addition to the Restoration Charges.

3.3.3 Technical Specifications for Restoration.—The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) Specifications for Road and Bridge Works and Indian Roads Congress (IRC) standards shall serve as the foundational guidelines for road restoration undertaken under the Dig

and Restore Method. The road safety and security shall be ensured by the applicant licensee as per IRC guidelines. Additionally, the road restoration guidelines of the concerned line department are to be followed by the CGD entity.

- 3.3.4 ***Dig and Restore Method for Pipeline Laying.***—Permission for laying underground gas pipelines will be granted exclusively under the Dig and Restore method. In the case of departmental restoration, the CGD entity shall pay the road restoration charges to the concerned line department as per the rates specified in Table 1. For self-restoration, the CGD entity shall submit a Performance Bank Guarantee amounting to 10% of the total road restoration cost, as indicated in Table 2, to the concerned line department. The security deposit, in case of self-restoration, will be released upon receipt of a No Objection Certificate (NOC) from the concerned authority of the line department, confirming satisfactory restoration by the CGD entity.

Permissions will be categorized into:

3.3.4.1 ***Departmental Restoration.***—

- Restoration will be undertaken by the department responsible for the construction, operation, and maintenance of the road.
- The cost for departmental restoration of roads will be calculated based on the "Rates for Departmental Restoration of Roads" as specified in Table 1, and the CGD entity shall deposit the amount in advance through the prescribed mode of payment.

3.3.4.2 ***Self-Restoration.***—

- Restoration will be carried out by the CGD entity itself.
- A Performance Bank Guarantee amounting to 10% of the total road restoration cost, as outlined in Table 2, shall be payable by the concerned CGD entity to the respective line department. The Performance Bank Guarantee shall be submitted prior to the commencement of actual work, preferably during the approval process for laying the pipeline by the concerned line department.
- The Performance Bank Guarantee (PBG) shall be released within 15 days of the issuance of the No Objection Certificate (NOC) by the concerned Additional District Nodal Officer or the Executive Officer of the Urban Local Body (ULB), confirming satisfactory completion of the road restoration work by the CGD entity.

For roads of significant importance, departmental restoration shall be the preferred option, subject to applicable conditions. The mode of payment for restoration charges shall be communicated by the concerned authority.

- 3.3.5 ***Implementation of Call before You Dig App*** with all departments as per GOI circular to be followed to avoid utility damage. The “Call Before You Dig” app will facilitate coordination between excavators and asset owners through SMS/email notifications and have click-to-call options. This will help in executing planned excavations and ensure that the concerned authorities are informed before any digging takes place.

- 3.3.6 ***Methods for Laying Underground Gas Pipelines.***—Open trench and trenchless method are allowed for laying underground gas pipeline works. However, Horizontal Directional Drilling (HDD) / Manual Milling method shall be considered by the entity wherever possible to reduce excavation / damage of roads for laying of Natural Gas pipeline.

- 3.3.7 **Road Damage Repair and Performance Bank Guarantee Validity.**— Damages to roads and filling of pits caused during the laying of underground gas pipelines shall be repaired by the concerned CGD entity within the specified time. A completion certificate or No Objection Certificate (NOC) will be issued by the concerned authority upon satisfactory restoration. The Defect Liability Period shall be for a duration of 12 months from the date of issuance of the Completion Certificate. The Performance Bank Guarantee shall initially be valid for a period extending 28 days beyond the Defect Liability Period.
- 3.3.8 The permission for laying the pipeline will be granted for the entire proposed pipeline network in one go, within the jurisdiction of the concerned District. However, the CGD entity is permitted to excavate no more than 20% of the total permitted length or 5 kilometres, whichever is less, at any given time. The CGD entity must submit a phased work plan to the concerned authority, with a copy to the District Nodal Officer. Upon satisfactory completion of the initial phase, the concerned CGD entity may proceed with excavation for the subsequent phase.
- 3.3.9 The CGD Entity shall deposit the Refundable Performance Bank Guarantee in advance for all the work proposed to be carried out as per the application submitted.
- 3.3.10 Laying of CGD Pipelines along and across Roads: In order to lay the pipelines along any road, the authorized Service Provider company can opt for either Open Cut Method or Molling method or Horizontal Directional Drilling (HDD) method. However, Open Cut method shall not be generally allowed for crossing of the State and National Highways and major Municipal Roads; and Horizontal Directional Drilling (HDD) method or Molling method only shall be followed therein. Open Cut method may be allowed for crossing only in case of minor rural roads with the permission of the concerned Executive Engineer of the Department/Agency of the State Government.
- 3.3.11 Laying of "Gas Pipeline" through Molling / HDD (Horizontal Directional Drilling) / Trenchless Method shall be allowed during monsoons, provided that the applicant takes all safety and security measures and plans for immediate restoration of the damage caused if any.
- 3.3.12 The number of gas pipelines to be laid under the roads in any stretch, for which permission is granted, shall be determined based on the requirements of the CGD entity. The concerned line departments (such as RCD/RWD) and the CGD entity shall collaborate to ensure the pipeline installation complies with technical and regulatory standards while minimizing disruptions to existing infrastructure.
- 3.3.13 The CGD Entity shall exercise utmost caution to prevent any damage to underground utilities during the laying of gas pipelines. In the event of any damage caused due to the negligence of the CGD Entity, it shall be solely responsible for rectifying the damage at its own cost. Furthermore, if any damage to the utility is caused by another agency due to incorrect identification of utility locations, the responsibility for rectification shall lie with that agency. Any disputes arising in this regard shall be reported to the District Nodal Officer for resolution.
- 3.3.14 Before commencing any road digging for pipeline installation, the CGD Entity shall obtain the route map and relevant details of existing underground utilities and installations, including water supply, sewerage systems, telecommunication lines, electricity supply, and other pipelines, while ensuring appropriate site supervision. To facilitate smooth

- coordination and minimize delays, each agency, department, authority, or entity with existing utilities in the proposed work area shall nominate a single point of contact (SPOC), with whom the CGD Entity shall coordinate directly to ensure the protection of underground utilities.
- 3.3.15 The CGD Entity shall also be responsible to intimate the concerned supervisory authority of such underground utilities before undertaking digging.
- 3.3.16 The cost of shifting existing underground utility & gas pipeline, wherever required, shall be borne by the requesting agency / authority/ CGD entity.
- 3.3.17 Each land or road-owning department shall appoint an Additional District Nodal Officer, not below the rank of Executive Engineer, to serve as the single point of contact for all CGD-related work within their jurisdiction. This officer will facilitate coordination, approvals, and oversight for CGD activities.
- 3.3.18 In case of shifting utility services due to road improvement/widening or construction of a flyover/bridge, the road-owning authority shall submit a detailed shifting proposal to the District Level Monitoring Committee. Based on the Committee's recommendation, the authority shall issue a notice for shifting. The shifting and restoration of utilities shall be carried out at the sole cost and risk of the CGD entities.
- 3.3.19 The CGD Entity shall designate a District-Level Nodal Officer to ensure effective coordination with the State Government and all relevant stakeholders.

3.4. **Applicability of State CGD Policy**

- 3.4.1 This Policy shall be applicable to all State Government department, state authorities, all land/road owning agencies including but not limited to Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Board in a Municipal area, industrial promotion bodies, Road Construction Department (RCD), Rural Works Department (RWD), Bihar Housing Board & Urban Development Authority in an urban area declared under the relevant law (excluding the Municipal area), and Gram Panchayat for Rural areas (excluding the area under the jurisdiction of an Urban, Improvement Trust or a Development Authority), Water Resource Department, Pollution Control Board, and all applicable bodies which involves in CGD network.
- 3.4.2 Any authorized licensee of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is eligible to seek / avail Right of Use (ROU) facility / permission. However, enforceability of the permission so granted shall be restricted to the extent of provisions/ scope of service contained/ defined in the license agreement of that licensee and for the purpose for which it is granted subject to compliance of the terms and conditions fixed by Government of India or any Competent Authority from time to time.
- 3.4.3 Either by content or by intent, the purpose of extending Right of Use facility / permission is not to enhance the scope of license of a licensee and such ROU permissions shall be only enabling in nature.
- 3.4.4 The responsibility to obtain No Objection Certificate from various Departments and Authorities, other than the State Government as and when required, shall be of the applicant licensee.
- 3.4.5 In cases where pipeline laying involves forest areas, the applicant licensee shall be solely responsible for obtaining a separate No Objection Certificate (NOC), if required, from the Forest Department, notwithstanding that the road may belong to State Government Departments, Local Bodies, or State Authorities. The extant guidelines

and regulations of the Government of India relating to the use of forest land shall apply in such cases.

3.5. **Application Submission for Right of Use/ Right of Way**

3.5.1 The application for permission to lay an underground gas pipeline shall be submitted to the Additional District Nodal Officer of the concerned line department, preferably the Executive Engineer of departments such as the Road Construction Department (RCD), Rural Works Department (RWD), Public Health Engineering Department (PHED), or any other applicable department responsible for the operation, maintenance, and development of the respective road. In areas under the jurisdiction of Urban Local Bodies (ULBs), the application shall be submitted to the Executive Officer of the concerned ULB.

3.5.2 ***Application Submission Requirements for CGD Pipeline Laying.***—The application must be submitted in the prescribed format (Common Application Form or CAF) and shall include:

- i. A copy of the authorization letter issued by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB).
- ii. A locality-wise route plan and Google Earth/AutoCAD map in “shapefile format (.shp)” or “Keyhole Markup Language (KML)” format. The map should detail the location, route, and land/property ownership where pipelines are to be laid.
- iii. Detailed work plan specifying the area-wise and time-wise schedule, along with the proposed methodology for laying pipelines (e.g., Horizontal Directional Drilling (HDD), open trenching, or both).
- iv. Information regarding the dimensions (length, width, depth) of the trench, depth of the pipeline, and other relevant specifications.
- v. The CGD entity shall also submit a soft copy of the application along with all the forms, statements, and documents.

3.5.3 ***Undertakings.—Undertakings by the applicant licensee confirming***

- i. All precautionary measures will be taken during pipeline laying to ensure safety of roads, vehicles, and road users.
- ii. Full liability for any hazards, damages, or leaks during pipeline operations, including repair costs and compensation.
- iii. Commitment to restore the road and surrounding areas to their original condition post-execution of work.
- iv. No utility service shall be laid over existing culverts and bridges, except through designated utility ducts where such provisions exist. In the absence of such provisions, the licensee shall make independent arrangements for crossing cross-drainage structures, rivers, etc., entirely at their own cost. In such cases, utility services may be carried outside the railings/parapets and bridge superstructure. The fixing and supporting arrangements, along with all technical details, shall require prior approval from the concerned administrative authority.
- v. Assurance to obtain all required environmental clearances or permissions if the project impacts ecologically sensitive areas.
- vi. Submission of additional details if requested by the permission issuing authority.
- vii. ***Penalty Acceptance.***—Failure to adhere to the undertakings will attract penalties, which may include suspension of work, revocation of permissions, and forfeiture of the Performance Bank Guarantee.

- 3.5.4 **Application Processing Timeline.**—The designated line department's Nodal Officer, not below the rank of Executive Engineer and Executive Officer in case of Urban Local Bodies, shall serve as the Additional District Nodal Officer and ensure that the application is processed within 15 days and under no circumstances later than 30 days from the date of submission of the application by the CGD entity. If permission is neither granted nor explicitly rejected within this 30-day period, the applicant licensee shall have the right to escalate the matter to the District Magistrate cum-District Nodal Officer for further review and consideration.
- 3.5.5 **Review of Pending Applications.**—The District Magistrate shall review all pending applications on a monthly basis to identify and address bottlenecks.
- 3.5.6 **Compliance.**—Authorized Service Providers must adhere to all relevant Acts, Rules, and Regulations prescribed by the State and Central Government, including compliance with the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962.
- 3.5.7 **Ownership.**—The CGD entity shall only have a Right of User (RoU) for operational purposes as per applicable laws. Ownership of the road or land where the pipeline is installed shall remain with the respective authority.
- 3.5.8 Upon granting digging and RoU permission, the Additional District Nodal Officer of the respective line department (such as RCD, RWD, PHED, etc.) shall notify the applicant CGD entity and mark a copy to the District Magistrate. Additionally, when granting RoU permission to other agencies in areas where a gas pipeline already exists, the Additional District Nodal Officer shall inform the CGD entity with an existing pipeline in the area and mark a copy of the RoU permission to the concerned CGD entity.
- 3.5.9 **Periodic Policy Review.**—This policy shall be reviewed periodically by the State City Gas Monitoring & Coordination Committee to incorporate stakeholder feedback, advancements in technology, and best practices.

3.6. **Application Disposal Procedure for Pipeline network laying**

- 3.6.1 The CGD entity shall submit the application to the Additional District Nodal Officer of the concerned line department, or in the case of Urban Local Bodies (ULBs), to the Executive Officer, with an advance copy to the District Magistrate. Upon receipt of the application, the Additional District Nodal Officer or the Executive Officer of the concerned ULB, as applicable shall prepare a Feasibility Assessment report and coordinate a joint inspection with the designated representative of the CGD entity within 15 days. Following the inspection, the necessary permissions may be granted to the CGD entity, subject to the submission of the Departmental Restoration Charges or Performance Bank Guarantee (PBG) in accordance with Table 1 or Table 2, the provision of all required documents, and the fulfilment of other relevant conditions as stipulated in this Policy.
- 3.6.2 **Feasibility Assessment Report Submission and Communication.**—The concerned line department, under whose control the proposed road lies, shall communicate the following with the requesting CGD entity for acceptance within fifteen (15) working days:
- The type of restoration proposed, whether to be carried out by the concerned department or by the requesting CGD entity.

- ii. The proposed method for laying pipelines—whether Open, Cutting Method, Horizontal Directional Drilling (HDD) and Molling Method.
- iii. The recommendation regarding the applicable Restoration Charges or Performance Bank Guarantee (PBG).

Upon receipt of this communication, the concerned CGD entity shall deposit the required PBG or Departmental Restoration Charges, as applicable, within seven (7) days.

3.6.3 Upon submission of the prescribed Restoration Charges and/or PBG, and the acceptance of the Feasibility Assessment report by the requesting CGD entity, the Additional District Nodal Officer shall grant the permission to lay the gas pipeline within one (1) month from the date the CGD entity submits the application.

3.6.4 ***Submission of Performance Bank Guarantee (PBG) or Restoration Charges.***—The applicant shall submit the necessary Performance Bank Guarantee (PBG) or restoration charges, as applicable, to the Additional District Nodal Officer of the concerned line department under whose jurisdiction the road lies. The applicant shall also provide a copy of the receipt of submission to the District Nodal Officer.

3.6.5 The Additional District Nodal Officer, not below the rank of Executive Engineer of the concerned line department, or the Executive Officer of the relevant Urban Local Body (ULB), as applicable, shall grant permission for pipeline laying within 7 (Seven) working days from the date of submission of the Performance Bank Guarantee (PBG) or payment of restoration charges and acceptance of the Feasibility report by the concerned CGD entity to the concerned Additional District Nodal Officer or the Executive Officer, as the case may be.

3.6.6 In the event that permission for RoU/RoW is not granted by the Additional District Nodal Officer or the Executive Officer of the Urban Local Body (ULB) within 30 (thirty) days of the initial application submission, the CGD entity may escalate the matter by submitting a formal representation to the District Nodal Officer, requesting expedited approval. The CGD entity shall not proceed with any pipeline laying activities until explicit authorization is obtained from the District Nodal Officer-cum-District Magistrate, in accordance with the prescribed procedures.

3.7. **No Objection Certificate:**

3.7.1 In the event of self-restoration by the CGD entity, the Additional District Nodal Officer of the concerned line department or the Executive Officer of the Urban Local Body (ULB), as the case may be, shall appoint a technical expert, not below the rank of Assistant Engineer, to inspect the restoration work and ensure adherence to the prescribed standards. The technical expert shall submit a report and issue the No Objection Certificate (NOC) upon satisfactory restoration. Based on the inspection report and the NOC, the Additional District Nodal Officer or the Executive Officer of the ULB, as the case may be, shall initiate the process for releasing the Performance Bank Guarantee (PBG) to the CGD entity within 15 days of granting NOC.

3.7.2 For arterial, sub-arterial, and other high-traffic roads, the entity responsible for excavation shall ensure that temporary restoration measures, including backfilling, compaction, and the application of a temporary road surface, are completed within 24 to 48 hours of the excavation. Permanent restoration for these roads shall be treated as a

- priority and must be completed within the timelines specified in the Common Application Form (CAF).
- 3.7.3 The entity after laying of pipeline & restoration thereon for the part of pipeline laid shall intimate in writing to the designated officer/ Additional District Nodal Officer for inspection of restoration & issuance of NOC.
- 3.7.4 The designated officer/ Additional District Nodal Officer shall inspect the work of restoration within 07 days of written intimation from the CGD entity and advise for rectification if any within 07 (seven) days.
- 3.7.5 The CGD entity shall rectify the restoration as per direction or the comments and intimate to the designated officer within 10 days.
- 3.7.6 The designated Officer/ Additional District Nodal Officer thereafter inspects the work again and issue NOC for restoration within 07 (seven) days.
- 3.7.7 If the NOC is not granted even after re-inspection & without any comments by the designated officer within 07 days of intimation by the entity for satisfactory restoration & inspection, the entity may represent the matter to the District Nodal Officer.
- 3.7.8 After the issuance of the No Objection Certificate (NOC) for the complete area under the jurisdiction of an authority, the concerned authority shall return the Performance Bank Guarantee (PBG) or, upon request of the concerned CGD entity, the same may be retained and treated as a PBG deposit for subsequent permissions.
- 3.7.9 The NOC issued by the designated authority/ Additional District Nodal Officer shall remain valid for a specified duration (e.g., one year) unless any substantial modification or damage to the restored area is observed or reported.
- 3.7.10 For minor modifications to the existing plot sizes of CNG stations to facilitate the installation of CNG equipment adjacent to an existing CNG station, the District Magistrate shall directly issue the No Objection Certificate (NOC) after due diligence. Since these Retail Outlets or CNG stations have already received clearances from the relevant authorities, the NOC process may be expedited with minimal additional scrutiny.
- 3.7.11 **Escalation Mechanism for Delay in Processing and Approval of Right of Use/Right of Way.**—This escalation mechanism outlines the process for addressing delays in the processing and approval of Right of Use (RoU) and Right of Way (RoW) permissions for City Gas Distribution (CGD) entities. The mechanism ensures timely approvals and clear accountability at each stage, with a structured escalation pathway.

| Stage | Responsible Authority | Timeline | Action | Escalation Point | Resolution Timeline |
|------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Application Submission | CGD Entity to Additional District Nodal Officer | Day 0 | Submission of RoU/RoW application | N/A | N/A |
| Joint Survey | Additional District Nodal Officer of the concerned line department/ Assistant Engineer and | Within 15 days of application submission | Conduct joint survey of the identified road | N/A | N/A |

| Stage | Responsible Authority | Timeline | Action | Escalation Point | Resolution Timeline |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|
| | CGD Entity Representative | | | | |
| Estimation of Road Restoration Charges | Additional District Nodal Officer | Within 15 days of application submission | Estimate road restoration charges based on the type of restoration and notify the CGD Entity | N/A | N/A |
| Deposit of Departmental Restoration Charges or PBG in case of self-restoration | CGD Entity | As per notification from Additional District Nodal Officer | Deposit the Road Restoration Charges or Performance Bank Guarantee (PBG) | N/A | N/A |
| Approval for Pipeline Laying | Additional District Nodal Officer | Within 30 days of application submission | Provide approval for laying the gas pipeline in accordance with policy terms and conditions | District Nodal Officer | Within 7days of escalation |
| Escalation to District Nodal Officer | District Nodal Officer | If approval is delayed beyond 30 days | Review and approve the pending application | State Nodal Officer | Within 10 days of escalation |
| Escalation to State Nodal Officer | State Nodal Officer | If issue remains unresolved beyond 40 days | Final review and resolution or response to the pending issue | N/A | N/A |

3.8. Land Allocation for District Regulating Stations (DRS), Metering and Regulating Stations (MRS), De-compression Units (DCU), Odorization Stations, City Gas Station (CGS) and Office Spaces for CGD Entities

3.8.1 Type of land considered for allotment:

- i. Purani Parti
- ii. Gair Mazarua (Aam, Khas & Malik)
- iii. Educational Institutes
- iv. Hospital Premises
- v. Nagar Nigam & Nagar Parishad
- vi. Khata
- vii. Road Construction Department/National Highway Authority of India/ Rural Works Department/ Water Resources Department/ Rural Development Department
- viii. Gram Panchayat
- ix. Block/ Anchal/Thana/ Jail Premises
- x. Transport department.
- xi. Industrial Authority
- xii. Electricity department
- xiii. All other type of land falls under any State Government department.

3.8.2 Demarcation of land.—The State Government and/or authority or the concerned line department shall have the right to declare any area or part of it to be reserved for a specific activity and in that case, that area or part of that would be allotted only for that specific activity, unless changed or de-

reserved by the Government authority.

The responsibility of identifying and proposing the land lies with the CGD entities. However, CGD entities may seek help of district administration in identifying the land.

3.8.3 *Competent authority for land allocation.*—The District Magistrate (DM) shall be the competent authority to allocate land to CGD entities for the establishment of District Regulation Stations (DRS), Meter Regulating Stations (MRS), and De-compression Units (DCU), Odorization Stations and Office Space for CGD entity. Such allocation shall be made in consultation with the concerned district-level officer of the land-owning department and shall be subject to obtaining the requisite clearance from the said department. The District Magistrate shall be authorized to allocate land up to a maximum of 500 square meters for each individual case.

3.8.4 *Process of application.*—The CGD entity shall submit an application to the District Nodal Officer, with an advance copy to the concerned local authority, for the installation of Pressure Regulating Stations, including but not limited to District Regulation Stations (DRS) (approx. 10m x 8m), Meter Regulating Stations (MRS), De-compression Units (DCU) (approx. 13m x 18m), Odorization Stations (20m x 18 m), City Gate Station (CGS) and , LNG/ L-CNG hub/ CBG (as per the norms- Area required) for CGD entities. The application must include the detailed design, safety protocols, technical specifications, estimated timelines for installation, a map marking the proposed location, and a copy of the authorization letter issued by PNGRB.

3.8.5 *Permission and Lease for Setting Up Pressure Regulating Stations.*—Permission for establishing Pressure Regulating Stations — including but not limited to District Regulation Stations (DRS), Metering Regulating Stations (MRS), or De-compression Units (DCU), Odorization Stations— shall be granted at strategic locations along the pipeline. These locations may encompass roadside areas, public parks, utility zones, Government premises, or other suitable sites, as identified in consultation with the concerned local authority and the City Gas Distribution (CGD) entity. The selection of sites shall prioritize public safety, ensure accessibility, and minimize disruption to existing infrastructure and public utilities.

To support the effective implementation of the City Gas Distribution (CGD) Network, land measuring 20 meters by 18 meters shall be earmarked for the establishment of odorization stations near the District Regulating Stations (DRS), in accordance with the mandate of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB). Odorization pumps will be installed at selected DRS locations based on operational requirements, without the necessity for every DRS to have an odorization pump. The allocation of land for these odorization stations shall be coordinated by the District Nodal Officer in consultation with the relevant line department responsible for the land.

The initial lease period shall be 25 years, with an annual lease rent set at 5% of the Minimum Valuation Register (MVR) of the residential category of land of that area, subject to necessary approvals. Lease rent payments shall be made annually on or before April 15 of each financial year or prior to the contract's expiration, whichever is earlier. The lease period may be further extended with the approval of the government.

Additionally, the annual lease rent charges shall be subject to revision every three years, based on the prevailing MVR of the residential category of land. The District Magistrate shall be the designated authority responsible for receiving lease rent payments from the concerned CGD entity.

- 3.8.6 ***Allocation of Government Land for Office Space.***—Subject to availability, Government land may be allocated to oil companies / CGD entity for the establishment of office spaces. The oil companies/ CGD entity shall bear all costs associated with the allotted land. Any structures developed on the Government land are likely to be permanent in nature. The allotment of land, along with the applicable rental or lease charges, shall be determined on a case-by-case basis.
- 3.8.7 District Magistrate shall ensure that specific provisions for plots of land for DRS station (10m X8M) or DCU station (13m x 18 m) are included in the Master plan for the respective areas. The State Government shall allot Government plots along the pipeline at any location including, but not limited to, roadside, Public Parks, Utility Areas, Government Premises, within municipal wards/villages etc. as per CGD entity requirement without any cost to reduce cost of PNG/CNG, which attract customers towards cleaner, cleaner fuel.
- 3.8.8 To further facilitate the CGD project, if no suitable Government land is available, the District Nodal Officer shall assist in identifying and securing appropriate private land through acquisition or lease agreements, ensuring the timely implementation of the CGD project while maintaining adherence to all applicable regulations and standards.
- 3.8.9 The District Nodal Officer shall direct the authority/ line department concerned for a joint survey alongwith the representative of CGD entity & shall submit the report within 15 days. The joint survey shall evaluate the suitability of the land, assess potential impacts on existing infrastructure, and ensure compliance with environmental regulations and public safety standards. The survey report must include detailed findings, accompanied by photographs and relevant supporting documentation.
- 3.8.10 On the receipt of the report from the concerned local authority/ Additional District Nodal Officer of the concerned line department, the District Nodal Officer shall decide the annual rent and shall intimate the entity with deposition of rent for an initial 3-year period and in multiples of 03 years there after.
- 3.8.11 The annual rent for land used for the installation of DRS/MRS/DCU shall be calculated at 5% of the Residential Reserve Price or the Residential DLC (District Level Committee) rate applicable to the area where the land is located. The "Residential Reserve Price / Residential DLC rate" shall be reviewed every three years, with adjustments made for inflation to ensure the rent remains reflective of fair market value.
- 3.8.12 The CGD entity shall deposit the rent to the concerned local authority and intimate the District Nodal Officer.
- 3.8.13 The District Nodal Officer will ensure the grant of permission for installation of Pressure Regulating Stations within 07 days from the date of deposition of rent to the local authorities concerned.
- 3.8.14 The registration charges while purchasing the land for DRS/MRS/DCU to be paid by CGD entity as per the Commercial land type and no further charges will be applicable for conversion of land from agriculture to commercial category for obtaining the Change of Land Use Certificate (CLU) certificate.
- 3.8.15 In case of temporary set-up of DCU required then short term lease, maximum a period of 5 years will be applicable till the time steel pipeline laid.

- 3.8.16 If the permission is not granted within 30 (Thirty) days from the date submission of application, the CGD entity may raise the issue with State Nodal Officer. The State Nodal officer will dispose of the application and recommend the District Nodal Officer concerned for granting the necessary permission within 7 days.
- 3.8.17 The lease deed shall be executed only after the final allotment of land and payment of yearly rental in advance.
- 3.8.18 The land will be allotted on lease for 25 years period on an As-Is, Where-Is basis with a provision of further extension.
- 3.8.19 In the event of any conflict arising, the District Magistrate shall act as the competent authority. The decision of the District Magistrate shall be final and binding on all parties involved.
- 3.8.20 If the allottee fails to pay the rent charges within the stipulated time, undertakes construction contrary to the approved plan, or engages in activities detrimental to industries, the District Magistrate, shall have the authority to cancel the land allotment.

3.9. Allotment of land for CNG Station

- 3.9.1 The CGD entities are committed to set-up certain fixed number of CNG retail outlets as part of Minimum Work Programme (MWP) committed to PNGRB during first 8 years from grant of authorization in their respective Geographical Areas.
- 3.9.2 District Nodal Officer shall ensure that specific provisions for plots of land for CNG stations are included in the master plan for the respective urban areas at key traffic corridors measuring (minimum 40m x 30m).
- 3.9.3 The allotment of land for the CNG station shall be granted by the District Magistrate on a case-by-case basis. The plots required for completing MWP at key traffic corridors within city limits, national highways, state highways, and other roads shall be allotted.
- 3.9.4 Necessary amendments must be made to the Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) for making provisions for allotment of plots of land for CNG stations.
- 3.9.5 Earmarking of land/plot for development of CNG stations at the planning stage of town/city and the same being specified in the Master Plan by Housing & Urban Deployment Authority.
- 3.9.6 Earmarking of land/plot for development of CNG stations at the planning stage of bus stands and the same being specified in the Master Plan by the Transport Department, Government of Bihar
- 3.9.7 ***Inclusion of Gas pipeline infrastructure in the road infrastructure of urban local bodies.***—The urban local authorities while executing road infrastructure projects including projects under Smart City and Tender SURE (specifications for urban roads execution), shall invariably include provisions for the gas pipeline infrastructure along with other utilities.
- 3.9.8 ***Provisions for the inclusion of PNG pipelines/networks by the local bodies at time of approval of building plan.***—Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall make necessary amendments to the by-laws for providing gas pipeline infrastructure in residential & commercial buildings at the plan approval stage. All the Government Quarters, Guest Houses, and Office buildings should have the provisions of PNG connectivity.
- 3.9.9 All the residential area buildings of Bihar Government shall use PNG. Modifying relevant building by-laws for providing gas pipeline infrastructure in residential & commercial buildings at architectural design stage.

3.10. **Promotion of CNG/LNG as preferred greener fuel**

- 3.10.1 Adoption of CNG/LNG as preferred transportation fuel with a view to promote usage of clean and green fuel in the transportation sector. State Transport Corporations accord priority to CNG/LNG buses while purchasing new buses and retrofitting in present alternate fuel fleet, in order to actively promote the usage of CNG/LNG in public transport. Efforts will be taken to convert vehicles being utilized/engaged in Government Departments (Cars, Buses, Ambulances, Delivery Vans, Goods Carrier, etc.) to CNG vehicles where CNG infrastructure is available.
- 3.10.2 ***Conversion of Diesel Generators in Government Buildings, Telecom service towers, Industries or other establishments in the Authorized area with gas generators.***—Telecom towers are located all over the Bihar state and draw primary and backup energy from a myriad of conventional sources. The Diesel Generator sets are polluting sources of power backup and leave a carbon footprint. With the expansion of the CGD network, a readily available alternative is to switch over from diesel-based generators to natural gas-based generators, especially in urban areas, which provide an environmentally friendly alternative, at a lower cost. The State Level committee will take steps to facilitate conversion of Diesel sets to CNG generators by bringing in appropriate rules/regulations.
- 3.10.3 ***Banning polluting fuels in the Industrial areas connected with Gas Pipeline Network.***—The Industrial areas must be encouraged to be connected by the gas pipeline network, In the Industrial areas where gas pipeline connectivity has been developed, all the polluting fuels may be banned. Further, a list of approved fuels in line with the Delhi NCR area may be adopted. The greater use of natural gas will bring down carbon emissions, helping the nation meet its COP-26 (Conference of the Parties) commitments.
- 3.10.4 ***Monitoring and Promoting CNG/LNG Adoption.***—The State Government will establish a monitoring and reporting framework to track the progress of CNG/LNG adoption in public transport, Government vehicles, and industrial areas. Regular assessments will be conducted to ensure compliance with the conversion goals, and corrective actions will be taken where necessary. Public awareness campaigns will also be conducted to encourage stakeholders to adopt CNG/LNG for cleaner, more sustainable energy solutions.
- 3.10.5 ***Marketing and awareness campaign.***—CGD entity will approach customers to create awareness among the public about the benefits of PNG and CNG through awareness campaigns, display of advertisements & hoardings on buildings, display of CNG direction markers on Highways.

3.11. **Grievance Redressal Mechanism**

- 3.11.1 The District Nodal Officer shall take a monthly review for all the complaints /grievances lodged by the public / Authority / CGD entity.
- 3.11.2 The complaint lodged by the public / Authority/ Line Department shall be forwarded to the concerned CGD entity within three (03) days and the CGD entity shall address the same and will submit compliance for each complaint within seven (07) days to the District Nodal Officer.
- 3.11.3 The complaints lodged by CGD entities to the District Nodal Officer shall be forwarded to concerned authorities within three (03) days and the concerned authority shall address the complaint and submit compliance to the District Nodal Officer within seven (07) days.

3.11.4 In the event that complaints or grievances lodged by the public, concerned authorities, or CGD entities are not resolved by the District Nodal Officer within the stipulated time period, such matters shall be escalated to the State City Gas Monitoring & Coordination Committee (SCGMCC) for further consideration and appropriate resolution.

3.11.5 **Dispute Resolution Mechanism.**—In the event of any dispute, disagreement, or difference arising between CGD entities and any line department of the Government of Bihar, or between CGD entities themselves, in connection with the implementation, operation, or interpretation of provisions under the City Gas Distribution Policy, all parties shall first make every effort to resolve the matter amicably through direct, informal negotiations.

If the dispute cannot be resolved through mutual negotiation within a period of thirty (30) days from the date on which one party notifies the other of the existence of such dispute, the matter shall be referred to arbitration. The dispute shall be referred to a sole Arbitrator appointed by mutual consent of the parties involved. In the event of failure to agree on a sole Arbitrator within thirty (30) days, the Arbitrator shall be nominated by the Law Secretary, Department of Law/Legal Affairs, Government of Bihar.

The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, and any subsequent amendments, re-enactments, or rules framed thereunder. The arbitral award shall be final and binding on all parties, subject to any legal remedies available under applicable laws. The venue of arbitration shall be Patna, Bihar, and the proceedings shall be conducted in English.

3.12. **Arrangement of Safety Measures at Work Site**

3.12.1 The CGD Entity shall take appropriate safety measures to ensure public safety during the establishment, post-establishment, maintenance, and other activities related to the laying of gas pipelines. It shall also implement necessary precautions to safeguard structures, including crossings over rivers and canals. In the event of any accident or damage to life or property during or after execution, the CGD Entity shall cooperate with the Local Authority to address and resolve the issue in accordance with applicable regulations.

3.12.2 **Restoration of Essential Services.**—In the event of damage to essential services by CGD entity such as water supply, sewerage systems, telecommunication lines, or electricity supply, the concerned CGD entity shall ensure the services are restored by the concerned service provider at the earliest. All costs incurred for the restoration shall be borne by the concerned CGD entity. The decision regarding restoration costs, as determined by the respective State Government Departments, Local Bodies, or State Authorities, shall be final.

The Emergency Response Vehicles (ERV) used by CGD Entities for responding to gas pipeline leaks, damage, or other emergencies shall be considered for designation as Emergency Vehicles by the Transport Department to facilitate prompt response and minimize delays.

3.12.3 **Compliance with Safety Standards.**—The CGD entity shall adhere to all safety standards and measures prescribed by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board or any other Competent Authority, as outlined in the terms and conditions of the NOC, approvals, or clearances. Any utility laid after the establishment of a gas pipeline network on a road shall be installed at a safe distance from the gas pipeline, with necessary safeguards as per applicable norms. If existing utilities are already present before the

gas pipeline is laid, the CGD Entity shall ensure the pipeline is installed with adequate safety precautions and necessary safeguards in compliance with the prescribed standards.

3.12.4 **Public Utility Status and Display of Notice.**—CNG mobile cascade carrier vehicles shall be treated as public utility vehicles. Additionally, the CGD Entity shall ensure that appropriate notices are displayed at the site before commencing any work.

3.12.5 **Open-Cut System Guidelines.**—When the gas pipeline is to be laid using an open-cut system, the area must be properly barricaded, and adequate shoring shall be provided. The work should be carried out in a manner that minimizes disruption to traffic. Road safety and security measures must be implemented by the licensee in accordance with IRC guidelines.

3.12.6 **Liability for Accidents, Damages, and Unauthorized Interference.**—The CGD Entity shall be held responsible for any accidents or damages resulting from its actions, omissions, or negligence during the execution or operation of the gas pipeline network. In the event of damage to the gas pipeline or related installations by an unauthorized person or entity, the CGD Entity may submit a written complaint, prompting the Police to take appropriate action as per the law.

Any unauthorized tampering or modification of the PNG system shall be subject to investigation by the relevant authorities, and if found to be caused by the consumer, the liability shall rest with them. Additionally, any obstruction, nuisance, or harm caused to CGD personnel by unauthorized individuals or entities during project execution or O&M activities shall be considered an offense against public utility service operations and addressed under relevant legal provisions.

3.12.7 **Emergency Response and Disaster Management.**—The District Authorities, in coordination with the concerned CGD entities operating within their respective Geographical Areas, shall be responsible for the preparation and periodic updating of Emergency Response and Disaster Management Plans. These plans shall specifically address potential risks such as gas pipeline leakages or damages. To ensure preparedness for such eventualities, the District Authorities and CGD entities shall jointly conduct mock drills at least once every year.

3.13. **Single-Window Online Portal for CGD Infrastructure Approvals**

3.13.1 To streamline the approval process for City Gas Distribution (CGD) infrastructure, a single-window online portal shall be developed and implemented by CGD entities within the next six months. This portal will serve as a centralized platform for submitting applications related to CGD infrastructure development.

The online system will facilitate the granting of various permissions at the district level, including Right of Use (ROU) permissions and land allotment for CNG stations, by the Additional District Nodal Officer and District Nodal Officer.

All relevant stakeholders at both the district and state levels will have access to the portal, with role-based permissions assigned to ensure an efficient, transparent, and structured approval workflow.

3.14. **Revision of Policy**

3.14.1. Based on the recommendations of the State City Gas Monitoring & Coordination Committee, the Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar, reserves the right to amend any clause or modify the provisions of this policy.

- 3.14.2 The Government of Bihar reserves the right to periodically review and adjust the charges, Performance Bank Guarantee amount, lease terms and related conditions, as necessary.
- 3.14.3 This policy shall come into effect from 15.07.2025, the date on which it is notified by the State Government.

PANKAJ KUMAR,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1257-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>